भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, आगरा (उ.प्र.) एवं धौलपुर (राजस्थान) से एक साथ प्रसारित

सच टाइम्स

DAINIK SACH TIMES

वर्ष 18 अंक 102 | मुरैना, मंगलवार 21 जुलाई 2026 | पृष्ठ - 8 मूल्य 1.50 ₹

समय-सीमा बैठक में प्रशासन सख्त

पेज : 03

प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी : आज के समय में प्रासंगिकता और नई शिक्षा की दिशा

पेज : 04

केंद्रीय विद्यालय में सुविधाओं के विस्तार को मिली मंजूरी, चिल्ड्रन पार्क, नया वाटर पॉइंट, कंप्यूटर और फर्नीचर होंगे उपलब्ध

पेज : 06

सोनम बंगचुग के समर्थन में मौ नगर में युवाओं का प्रदर्शन

पेज : 07

मासूम बच्चों अव्यक्त और प्रेक्षा के परिजनों के साथ है सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले डाक सहायक स्व. उर्मिला सैनी के परिजन, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी स्व. उर्मिला सैनी के बच्चों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर की डाक सहायक स्व. उर्मिला सैनी के मासूम बच्चों की स्कूली एवं उच्च शिक्षा की पढ़ाई-लिखाई के लिये 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मानवीय संवेदना जताते हुए इंदौर में घटित दुघर्टना में मासूम अव्यक्त (उम्र 7 वर्ष) और प्रेक्षा (उम्र 15 वर्ष) के सर से माँ श्रीमती उर्मिला सैनी का साया उठने के बाद मासूम बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मासूम प्रेक्षा ने नाना श्री सत्यनारायण मालाकार और अन्य परिजनों के साथ विधानसभा स्थित कक्ष में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे स्वयं को बिल्कुल भी अकेला न समझें। सरकार मासूम बच्चों की शिक्षा के लिये हरसंभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बच्चों के नाम 5 लाख रूपये की एफडी होगी। एफडी की ब्याज की राशि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में व्यय की जायेगी।

मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने सांसदों से की सार्थक चर्चा की अपील

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को मानसून सत्र से पूर्व सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही में बढ़-कर कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तर्क और तथ्य मजबूत होने पर शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संसद की जिम्मेदारी है कि चर्चा समृद्ध हो, हर आवाज को स्थान मिले और हर विचार को सम्मान मिले। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। प्रत्येक सत्र से पहले प्रधानमंत्री परंपरागत रूप से संसद परिसर में मीडिया को संबोधित कर सरकार की प्राथमिकताओं और सत्र के प्रति अपनी अपेक्षाएं साझा करते हैं।

उन्होंने मानसून सत्र की तुलना वर्षा ऋतु मानसून से की और कहा कि दोनों के सक्रिय होने पर उत्पादकता में वृद्धि आती है। इससे एक तरफ देश का और दूसरी तरफ जीव मात्र का कल्याण होता है। उन्होंने दोनों के सक्रियता की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अब विकास की

नई गति हासिल कर ली है और संसद अपनी सकारात्मक सोच के साथ मानसून सत्र में इसमें और ऊर्जा भर सकता है। उन्होंने कहा कि संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना और देश को आगे ले जाने का प्रयास समय की मांग है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचारों को सदन में स्थान मिलता रहे यह हम सब की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां हासिल की हैं जिसने देशवासियों को गौरवान्वित किया है।

संक्षिप्त समाचार

अहमदाबाद की अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट में एक घायल की मौत, मृतकों की संख्या 10 हुई

अहमदाबाद, 20 जुलाई (हि.स.)। गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्राल क्षेत्र स्थित अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। हादसे में 95 प्रतिशत तक झुलसे एक घायल ने सोमवार तड़के सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल चार घायलों का इलाज जारी है, जिनमें एक महिला की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि हादसे के बाद पांच घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें एक महिला और चार पुरुष शामिल थे। इनमें एक पुरुष 95 प्रतिशत से अधिक तथा महिला 75 प्रतिशत से अधिक झुलस गई थी। दोनों की हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। डॉ. जोशी के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 2:15 बजे 95 प्रतिशत तक झुलसे पुरुष मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे बचाने के लिए डॉक्टरों ने हरसंभव प्रयास किए, लेकिन गंभीर जलने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने बताया कि अस्पताल के बर्न्स वार्ड में अभी जो मरीज भर्ती हैं। इनमें एक 40 प्रतिशत और दूसरा 20 प्रतिशत तक झुलसा है।

उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, 24 घंटे में तीन की मौत; यमुनोत्री हाईवे अब भी बंद

देहरादून, 20 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पिछले 24 घंटों में प्राकृतिक आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मलबा, बोल्डर गिरने और जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-134) पालीगाड़ के पास मलबा आने के कारण अब भी बंद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) की सोमवार को जारी 24 घंटे की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के पोषिला गांव में जंगल में बकरियां चरा रहे 52 वर्षीय दीवान सिंह की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। नैनीताल जिले के हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैदल यात्री की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। टिहरी जिले के प्रतापनगर-लंबगांव मोटर मार्ग पर एक कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में चालक 38 वर्षीय होशियार सिंह पंवार, निवासी खोलगढ़, गंभीर रूप से घायल हो गए।

युवाओं पर कार्रवाई का हवाला देकर सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का किया ऐलान

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ हुई कथित बर्बरता को देखते हुए उन्होंने अनशन समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार और पुलिस से छात्रों को संसद के समक्ष अपनी शिकायतें रखने की अनुमति देने की अपील की है। सोनम वांगचुक ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल से जारी हस्तलिखित संदेश में कहा कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती या उन्हें स्वयं अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। वांगचुक ने कहा कि उकसावे के बावजूद युवाओं ने जिस संयम और शांति का परिचय दिया है, उससे वे भावुक और प्रभावित हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा प्रदर्शनकारी आगे भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखेंगे। उल्लेखनीय है कि वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं अन्य मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनशन पर हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हमारी मांगों पर सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, जंतर-मंतर (केरल हाउस के बाहर) पर विरोध प्रदर्शन जारी है।

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल 65 लोग आरएमएल अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 65 लोगों को राममनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में भर्ती कराया गया है। इनमें प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आरएमएल अस्पताल प्रशासन के अनुसार शाम 7 बजे तक सर्जरी विभाग में कुल 65 मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) लाए गए। इनमें प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है, जबकि मामलों की विस्तृत जानकारी का इंतजार है। इसके अलावा भूख हड़ताल पर बैठे 10 लोगों का भी एमएलसी बनाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी अनशनकारियों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रदर्शन में घायल हुए लोगों का अस्पताल आना जारी है।

दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की ममता बनर्जी ने की निंदा, बोलीं- लोकतंत्र में लाठी नहीं, संवाद होना चाहिए

कोलकाता, 20 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली में छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सवालों का जवाब लाठीचार्ज और आंसू गैस से नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में कहा कि देश छात्रों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और प्रत्येक नागरिक का है। उन्होंने कहा कि असहमति व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, पुलिस बल का प्रयोग सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता।

छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के खिलाफ : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट-यूजी समेत विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं। अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना और आंसू गैस का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

राहुल गांधी ने सोमवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, लेकिन सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर उतरे छात्र अपराधी नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सम्मानजनक, निष्पक्ष और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था मिले। कांग्रेस नेता ने कहा कि छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी तरह जायज है। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ना और लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और न ही यह भारत की परंपरा के अनुरूप है। सरकार को छात्रों की मांगें स्वीकार कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

भारत-मोल्दोवा के बीच कृषि, स्वास्थ्य, एआई समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी तीन देशों की राजकीय यात्रा के पहले चरण में सोमवार को मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ में राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने कृषि, स्वास्थ्य, औषधि, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवाचार, लॉजिस्टिक्स और आधारभूत ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मु रविवार को चिशिनाउ पहुंचीं। उनके साथ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया, राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा और लोकसभा सदस्य विजय

बघेल भी हैं। चिशिनाउ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मिहाई पोपशोई ने उनका स्वागत किया।

बाद में राष्ट्रपति मुर्मु मोल्दोवा के राष्ट्रपति भवन पहुंचीं, जहां मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू ने उनका औपचारिक स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच एकांत वार्ता और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं पर व्यापक और भविष्य उन्मुख चर्चा की गई।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय मोल्दोवा यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह भारत और मोल्दोवा के बीच बढ़ती मित्रता तथा आपसी विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों देशों के बीच पिछले तीन दशकों से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और शांति, विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साझा मूल्यों ने इस साझेदारी को निरंतर मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने, संपर्क बढ़ाने तथा दोनों देशों के कारोबारी समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

देश को मिली पहली डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा', सीडीएससीओ ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)। डेंगू की रोकथाम की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारतीय दवा नियामक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जापान की दवा कंपनी टाकेडा द्वारा विकसित यह वैक्सीन भारत में डेंगू से बचाव के लिए स्वीकृत होने वाली पहली वैक्सीन है। सीडीएससीओ की मंजूरी के बाद यह वैक्सीन 04 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को लगाई जा सकेगी। इसकी खास बात यह है कि टीका लगवाने से पहले यह जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ है या नहीं। यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रमुख प्रकारों (सीरोटाइप) से सुरक्षा देने के लिए विकसित की गई है। कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार, दूसरी डोज के एक साल बाद तक यह वैक्सीन पुष्टि किए गए डेंगू मामलों के खिलाफ लगभग 80 प्रतिशत प्रभावी पाई गई। वहीं, गंभीर डेंगू के मामलों में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम भी काफी कम देखा गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस वैक्सीन की मंजूरी भारत में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को नई मजबूती देगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वैक्सीन के साथ-साथ मच्छरों की रोकथाम, साफ-सफाई और जलभराव रोकने जैसे उपाय भी डेंगू नियंत्रण के लिए उतने ही महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामें के चलते कार्यवाही रही प्रभावित

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.स.)। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन सोमवार को विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, नीट एवं अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दे समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। अंततः दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इसी बीच लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय में

न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने संबंधी 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया गया। वहीं राज्यसभा में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान के समान सम्मान देने से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। संसद परिसर के बाहर भी विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और संसद भवन की ओर आने-जाने वाले मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही अध्यक्ष ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी सहित छह पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर तीन बार थोड़े अंतराल के लिए स्थगित होने के बाद तीन बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इसी दौरान केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। दूसरी ओर राज्यसभा में मानसून सत्र के पहले दिन नौ नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इनमें गुजरात से मुकेशभाई जे. राठवा, कर्नाटक से पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से महेश केवट, मेघालय से जेम्स पांगसांग कोंगकल संगमा, मिजोरम से खियांगते ललतलुआगकिमा, राजस्थान से सतीश पूनिया तथा पश्चिम बंगाल से प्रकाश चिक बराइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय शामिल हैं।

स्वामी एवं प्रकाशक रविन्द्र सिंह नवरंग द्वारा वनखंडी रोड़ हरीराज टॉकीज के पीछे, शिवनगर मुरैना (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित एवं मुद्रक नवीन बंसल द्वारा बंसल ऑफसेट रामजानकी मंदिर के पास, जीवाजीगंज मुरैना से मुद्रित, स्थानीय संपादक- धर्मेंद्र सिंह ''सीताराम जी '', मुरैना, मोबाइल 6261839476
RNI No. MPHIN/2009/45558 फोन 07532-232387 मोवा- 9425334744 तथा सभी विवादों को न्याय क्षेत्र मुरैना ही होगा। डाक पंजीयन चंबल क्रमांक जी-13-2/163/RNP/2025-27, email : sachtimes101@gmail.com

एमपी ऑनलाइन ने उत्कृष्ट विद्यालय मुरैना को दी मिनी साइंस सेंटर की सौगात

मुरैना (निज संवाददाता)। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1, मुरैना में सोमवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल के सहयोग से स्थापित मिनी साइंस सेंटर का विधिवत लोकार्पण किया गया। इसी अवसर पर विद्यालय में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर लैब का भी शुभारंभ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी. एस. इंदोलिया थे, जबकि एमपी ऑनलाइन की डीईजी हेड श्रीमती आरती श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य श्री मुकेश कुमार शांडिल्य ने की। इस अवसर पर जिला व्यावसायिक शिक्षा समन्वयक श्री आलोक कुमार वर्मा सहित एमपी ऑनलाइन के श्री लक्ष्मण साहू, श्री नितेश ठाटे, श्री शैलेंद्र डंडोतिया, श्री रघुराज तोमर एवं श्री विवेक शर्मा उपस्थित रहे।

प्राचार्य श्री मुकेश कुमार शांडिल्य ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि विद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक एवं कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और रचनात्मक सोच को विकसित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

मुख्य अतिथि श्री बी. एस. इंदोलिया ने अपने संबोधन में कहा कि एमपी ऑनलाइन द्वारा स्थापित मिनी साइंस सेंटर मुरैना जिले के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और गणित को प्रयोगों के माध्यम से सीखने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ेगी और उनकी अवधारणाएँ अधिक स्पष्ट होंगी।

श्रीमती आरती श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि एमपी ऑनलाइन का उद्देश्य विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों को तकनीकी, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें।

लोकार्पण के उपरांत अतिथियों ने मिनी साइंस सेंटर में स्थापित लगभग 80 कार्यशील विज्ञान एवं गणित मॉडलों का अवलोकन किया। विद्यालय के गणित शिक्षक डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने पाइथागोरस प्रमेय सहित विभिन्न गणितीय मॉडलों की कार्यप्रणाली का सजीव प्रदर्शन करते हुए बताया कि इन मॉडलों के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को भी विद्यार्थी सहजता से समझ सकते हैं। इसके पश्चात विद्यालय की विज्ञान शिक्षिका श्रीमती सुषमा राजपूत ने विज्ञान से संबंधित विभिन्न मॉडलों का प्रदर्शन करते हुए उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं व्यवहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। दोनों शिक्षकों की प्रस्तुति की अतिथियों ने मुक्तकंठ से सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर लैब का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री प्रेम कुमार पाराशर (लैब प्रभारी), श्री सुनील पाराशर, श्री संदीप सिंह तोमर, श्री तपेश्वर भारद्वाज, श्री मुकेश कुमार, श्री दिव्यव्रत शर्मा, श्री सुनील सिंघल, श्री भानु पचौरी, श्री बी. के. कुशवाह, प्रिन्स शर्मा एवं श्री राजू कुशवाह सहित विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंत में सभी अतिथियों ने विद्यालय परिवार को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एमपी ऑनलाइन द्वारा स्थापित मिनी साइंस सेंटर तथा विद्यालय की इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर लैब विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी दक्षता, नवाचार एवं शोध की भावना को नई दिशा प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं आयोजन विद्यालय परिवार के सहयोग से संपन्न हुआ। विद्यालय परिवार ने एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल तथा सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि यह पहल विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित एवं तकनीकी शिक्षा में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

पीएम आवास योजना 2.0 में बड़ा विवाद!

रंजिश में गरीबों के सपनों पर चला बुलडोजर

ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब प्रधानमंत्री आवास योजना (क्क2ड्ढ 2.0) के सत्यापन पर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। जनपद पंचायत श्योपुर की ग्राम पंचायत बड़ौदाराम के सीसवाली गांव के गरीब परिवारों ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण उन्हें पात्र होने के बावजूद अपात्र घोषित कर दिया गया, जिससे उनके पक्के घर का सपना टूट गया।

पीड़ित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा पात्र परिवारों को तत्काल योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पीएम आवास योजना 2.0 के सत्यापन के दौरान जांच अधिकारी रामदयाल राठौर, सचिव कैलाश आर्य एवं रोजगार सहायक सुरेश जाटव ने मनमानी करते हुए जानबूझकर पात्र हितग्राहियों को अपात्र घोषित कर दिया। उनका कहना है कि वे वर्षों से कच्ची और जर्जर झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन निजी रंजिश के कारण उन्हें सरकारी योजना से वंचित कर दिया गया।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने दावा किया है कि रोजगार सहायक द्वारा पहले ही उन्हें यह कहकर धमकाया गया था कि 'मेरे रहते तुम्हें कभी आवास नहीं मिलेगा।' अब सत्यापन सूची में नाम काटे जाने के बाद ग्रामीणों ने इसे उसी कथित रंजिश का परिणाम बताया है।

'टपकती झोपड़ियों में गुजर रही जिंदगी ': पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। बारिश के दिनों में झोपड़ियों में पानी भर जाता है और पूरा परिवार जान जोखिम में डालकर जीवन बिताने को मजबूर है। उनका कहना है कि सरकार गरीबों के लिए आवास योजना चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मनमानी के कारण वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच रहा।

इन परिवारों ने लगाई न्याय की गुहार

ज्ञापन में जिन लोगों को पात्र होने के बावजूद अपात्र घोषित किए जाने का आरोप लगाया गया है, उनमें बाबूलाल, रामसिंह, राकेश, महेंद्र, हेमराज, बाबूलाल, रामप्रसाद, राजेश, महावीर, जुगराज एवं महेंद्र बैरवा सहित कई गरीब परिवार शामिल हैं।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा की जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी पात्र परिवारों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की सूची में जोड़े जाएं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

श्योपुर में फिर दहशत

जंगल से लौट रहे दो पशुपालकों का कथित अपहरण, हथियारों के दम पर लूट... पुलिस पहुंची तो बदमाश बंधक छोड़ जंगल में फरार

जिला ब्यूरो संगीता गुप्ता

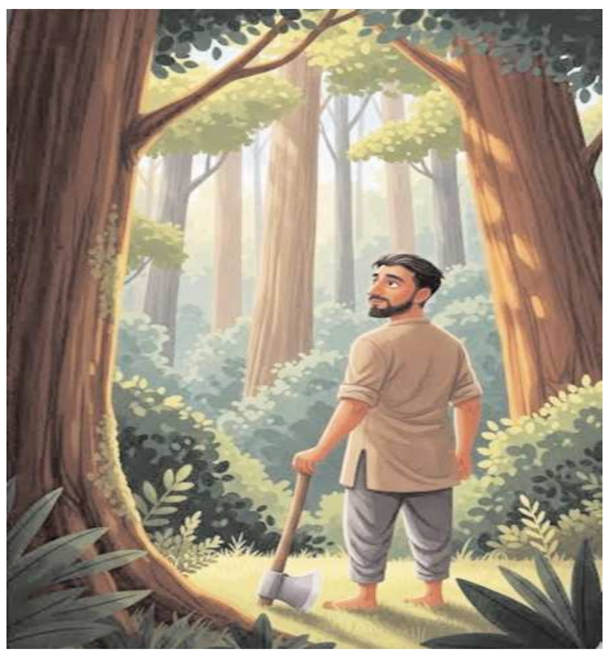

श्योपुर। जिले में अपराधों का ग्राफ लगातार चिंता बढ़ा रहा है। ताजा मामला विजयपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां शनिवार शाम जंगल से अपने मवेशियों के साथ लौट रहे दो पशुपालकों को दो हथियारबंद बदमाशों ने कथित रूप से अगवा कर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने दोनों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर उनके पास रखी नकदी, मोबाइल फोन और सोने की बाली लूट ली। इसके बाद बदमाशों ने एक पशुपालक को 50 हजार रुपये की फिरौती लाने के लिए छोड़ दिया, जबकि दूसरे को अपने कब्जे में रखा।

घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही छोड़े गए पशुपालक ने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी, विजयपुर थाना पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और पुलिस टीम जंगल की ओर रवाना हो गई। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही बदमाश बंधक बनाए गए दूसरे पशुपालक को छोड़कर घने जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।

यह सनसनीखेज घटना कलपत बाबा के स्थान के समीप स्थित जंगल में हुई बताई जा रही है। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार दोनों पशुपालक रोज की तरह जंगल से लौट रहे थे, तभी रास्ते में हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पहले उनके साथ मारपीट और धमकी दी गई, फिर कीमती सामान लूट लिया गया। इसके बाद फिरौती की मांग ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जंगल से लगे क्षेत्रों में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे पशुपालकों, किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

उधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह घटना एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो जंगल और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन और अधिक असुरक्षित हो जाएगा।

पॉक्सो कानून पर जिला न्यायालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बच्चों की सुरक्षा, त्वरित न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकारों पर दी गई विस्तृत

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिला न्यायालय परिसर स्थित पॉक्सो विशेष न्यायालय में सोमवार को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बी.एल. प्रजापति के मार्गदर्शन में विधिक एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के प्रति आमजन, पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को जागरूक करना तथा बाल संरक्षण संबंधी कानूनी अधिकारों की जानकारी देना था।

कार्यक्रम में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बबीता होरा शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों में कानून अत्यंत संवेदनशील एवं कठोर है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चों की पहचान गोपनीय रखी जाती है तथा उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, आवश्यक चिकित्सीय सुविधा और मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था कानून में सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने पॉक्सो मामलों की त्वरित सुनवाई, पीड़ितों के अधिकारों तथा न्यायालय की संवेदनशील भूमिका पर भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (ड्डक्ष्ह्र) की 'बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता एवं उनके संरक्षण की योजना' की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बालक को न्याय सुलभ कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से अपील की कि यदि किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक अपराध या उत्पीड़न की जानकारी मिले तो उसे छिपाने के बजाय तत्काल संबंधित पुलिस अथवा सक्षम प्राधिकरण को सूचित करें, ताकि पीड़ित को समय पर सुरक्षा और न्याय मिल सके।

इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनदीप कौर सेहमी, जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता शांडिल्य, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं न्यायालय परिसर में उपस्थित अन्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पॉक्सो कानून से जुड़े विभिन्न प्रश्न भी पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा विस्तारपूर्वक समाधान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि भविष्य में भी आमजन, विद्यार्थियों एवं विभिन्न संस्थानों में इस प्रकार के विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि समाज में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़े और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो सके।

रक्षाबंधन मेला 2026 की तैयारियों को लेकर अग्रवाल संघ मुरैना की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

मुरैना (निज संवाददाता)। अग्रवाल संघ मुरैना द्वारा 7, 8 एवं 9 अगस्त 2026 को गांधी मैरिज होम में आयोजित होने वाले रक्षाबंधन मेले की तैयारियों को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मेले के सफल एवं भव्य आयोजन के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मेले की सुरक्षा, स्वच्छता, पार्किंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों एवं महिलाओं की गतिविधियों, खान-पान, स्टॉल व्यवस्था तथा आगंतुकों की सुविधाओं को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मेले को पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक आकर्षक, सुव्यवस्थित एवं जनसहभागिता से परिपूर्ण बनाने का संकल्प लिया।

मेला समिति के संयोजक राहुल गोयल ने तैयारियों की जानकारी देते हुए सभी सदस्यों से सक्रिय सहयोग की अपील की। सह संयोजक पवन गर्ग ने विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव प्रस्तुत किए। महिला प्रकोष्ठ की ओर से श्रीमती प्रभा अग्रवाल एवं श्रीमती माला गर्ग ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने तथा उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर अपने विचार रखे।

बैठक में अग्रवाल सघं के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नालाल अग्रवाल, जिलाध्यक्ष रामदास बंसल, जिला महामंत्री राजेश मित्तल, जिला मंत्री माधव गोयल जगदीश अग्रवाल।

उपाध्यक्ष दिलीप बंसल कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिर्जेश गर्ग, उपाध्यक्ष अशोक मंगल सहित संघ के अनेक पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने रक्षाबंधन मेले को सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत एवं पारिवारिक सौहार्द का प्रतीक बनाते हुए इसे भव्य, सफल एवं यादगार बनाने का संकल्प लिया। अग्रवाल संघ ने समाज के सभी नागरिकों से 7, 8 एवं 9 अगस्त को गांधी मैरिज होम में आयोजित होने वाले रक्षाबंधन मेले में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने की अपील भी की।

36 घंटे टावर पर डटी महिला, प्रशासन बोला- परियोजना की भूमि से नहीं है संबंध; 782 करोड़ की चंबल मल्टी विलेज योजना की कार्रवाई रुकी

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। श्योपुर जिले की महत्वाकांक्षी 782 करोड़ 11 लाख रुपये लागत वाली चंबल मल्टी विलेज पेयजल परियोजना इन दिनों एक महिला के टावर पर चढ़ने की घटना के कारण चर्चा का विषय बन गई है। एक ओर श्रीमती रामा रावत अपनी पैतृक भूमि के सीमांकन और वैधानिक कब्जे की मांग को लेकर पिछले 36 घंटे से अधिक समय तक बीएसएनएल मोबाइल टावर पर डटी रहीं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि महिला का उस शासकीय भूमि से कोई स्वामित्व या कब्जा संबंध नहीं है, जिस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना है।

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि विवाद और जनसुनवाई प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

महिला का आरोप– न्याय नहीं मिला, इसलिए टावर पर चढ़ना पड़ा

वीरपुर तहसील के ग्राम लीलदा निवासी रामा रावत, पत्नी बाबूलाल रावत का कहना है कि उनकी पैतृक भूमि के सीमांकन और वैधानिक कब्जे के लिए लंबे समय से राजस्व विभाग के चक्कर लगाए जा रहे हैं। कई आवेदन, शिकायतें और गुहार लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन सीमांकन कर वैधानिक कब्जा दिला देता तो उन्हें यह कदम नहीं उठाना पड़ता। परिवार ने चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। यदि महिला के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

तहसीलदार ने सीमांकन के आदेश भी किए जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार वीरपुर ने 19 जुलाई को आदेश जारी कर 20 जुलाई को सीमांकन कराने के लिए राजस्व निरीक्षक एवं कई पटवारियों का दल गठित किया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।

हालांकि परिवार का आरोप है कि आदेश जारी होने के बावजूद मौके पर उन्हें वास्तविक न्याय नहीं मिला, इसलिए महिला टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई।

प्रशासन का पक्ष— महिला का परियोजना की भूमि से कोई संबंध नहीं

जिला प्रशासन ने पूरे मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई चंबल मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत ग्राम श्यारदा में बनने वाले 71.44 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवंटित 7.420 हेक्टेयर शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए की जा रही थी।

प्रशासन के अनुसार यह भूमि 7 जनवरी 2025 को पीएचई विभाग को आवंटित की गई थी। इस भूमि पर कुछ लोगों का कब्जा होने के कारण 19 मई 2026 को राजस्व न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया था। इसके बाद 19 जुलाई 2026 को एसडीएम, पुलिस प्रशासन, राजस्व अमला एवं पीएचई-जल जीवन निगम की संयुक्त टीम सीमांकन और कब्जा हस्तांतरण की कार्रवाई कर रही थी।

इसी दौरान रामा रावत बीएसएनएल टावर पर चढ़ गईं, जिससे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कार्रवाई रोकनी पड़ी।

प्रशासन का कहना है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार रामा रावत या उनके पति बाबूलाल रावत का इस आवंटित भूमि पर कोई स्वामित्व अथवा कब्जा दर्ज नहीं है। उनका नाम अन्य सर्वे क्रमांक 131 की भूमि पर दर्ज है। प्रशासन ने यह भी कहा कि महिला के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद विधिवत भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

385 गांवों की पेयजल योजना प्रभावित

प्रशासन के अनुसार यह परियोजना जिले की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, जिसके माध्यम से श्योपुर जिले के लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र के 385 गांवों की 8 लाख 23 हजार 272 ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही परियोजना से स्थानीय स्तर पर 500 से 600 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है।

महिला के टावर पर चढ़ने के कारण फिलहाल भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई प्रभावित हुई है।

ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन पर सवाल

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते विवादों का समाधान करता तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता।

दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि वह लगातार समझाइश और वार्ता का प्रयास कर रहा है तथा महिला की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल...

पूरा मामला अब दो अलग-अलग दावों के बीच खड़ा है। एक ओर महिला और उसका परिवार वर्षों से न्याय न मिलने का आरोप लगा रहा है, वहीं प्रशासन का कहना है कि जिस भूमि पर परियोजना बननी है, उससे महिला का कोई वैधानिक संबंध नहीं है।

ऐसे में अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि क्या महिला की शिकायत का अलग से समाधान होगा और क्या करोड़ों रुपये की पेयजल परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। साथ ही यह प्रश्न भी बना हुआ है कि भविष्य में ऐसे विवादों का समय रहते समाधान कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी नागरिक को अपनी बात मनवाने के लिए जान जोखिम में डालने जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

समय-सीमा बैठक में प्रशासन सख्त

16वें दिन अपने आप लगेगी पेनल्टी, छात्रावास निरीक्षण और खाद वितरण पर भी दिए कड़े निर्देश

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देशानुसार सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब महंगी पड़ेगी। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के 15 दिन बाद 16वें दिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित पदाभिहित अधिकारी पर स्वतः पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए सभी अधिकारी लंबित आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक में एसडीएम गगन सिंह मीणा, एसडीएम कराहल बीएस श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य, नवागत डिप्टी कलेक्टर पवन घुरैया सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।

छात्रावासों की व्यवस्था पर विशेष फोकस, इसी सप्ताह निरीक्षण अनिवार्य

बैठक में अपर कलेक्टर ने हाल ही में छात्रावासों के निरीक्षण में सामने आई व्यवस्थागत कमियों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि जिन जिला स्तरीय अधिकारियों को छात्रावास एवं आश्रमों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे नियमित भ्रमण करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी इसी सप्ताह अपना पहला निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

खाद वितरण पर सतर्क प्रशासन, पर्याप्त स्टॉक होने का दावा

खरीफ सीजन को देखते हुए बैठक में उर्वरक उपलब्धता की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद के भंडारण एवं वितरण पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा किसी भी किसान को खाद के लिए परेशान न होना पड़े।

बैठक में जानकारी दी गई कि–

47 सहकारी समितियों पर खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

अब तक 16,079 किसानों को समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरित किया जा चुका है।

जिले में 31,429 किसान ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से खाद प्राप्त कर चुके हैं।

विभिन्न भंडारण केंद्रों पर 19,076 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है।

प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुचारु बनी रहे।

सीएम हेल्पलाइन में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले की वर्तमान निराकरण प्रगति 78.62 प्रतिशत है। अपर कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि ग्रेडिंग जारी होने से पहले अधिकतम शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए, ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके।

श्रमिकों का पंजीयन भी प्राथमिकता

बैठक के दौरान सभी निर्माण विभागों को प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पात्र श्रमिकों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

समय-सीमा बैठक में प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि अब लोक सेवा गारंटी, छात्रावास व्यवस्था, खाद वितरण और सीएम हेल्पलाइन जैसे मामलों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए समयबद्ध कार्य संस्कृति लागू करने पर विशेष जोर दिया गया।

सुविधाओं के अभाव का हवाला देकर प्रसूता को किया रेफर

अस्पताल से निकलते ही सड़क पर हुई डिलीवरी

वायरल वीडियो ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योप्पुर। एक ओर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, निःशुल्क प्रसव सेवाएं, 108 एंबुलेंस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर लापरवाही और अव्यवस्थाएं इन प्रयासों पर सवाल खड़े कर रही हैं।

ऐसा ही एक मामला श्योपुर जिले के ढोढर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को कथित रूप से अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने और ऑपरेशन की आवश्यकता बताकर रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल से कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही प्रसव पीड़ा तेज हो गई और महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया।

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

परिजनों का आरोप— ऑपरेशन बताकर भेज दिया, रास्ते में हो गया सामान्य प्रसव

प्रसूता के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ ने उन्हें बताया कि महिला की डिलीवरी सामान्य रूप से संभव नहीं है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह कहते हुए उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

लेकिन जैसे ही वाहन अस्पताल से कुछ दूरी पर पहुंचा, महिला की प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई और बीच रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। परिजनों का कहना है कि यदि अस्पताल में समय पर उपचार और प्रसव कराया जाता तो महिला और नवजात को इस तरह जोखिम में नहीं डालना पड़ता।

वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल

घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव जैसी बुनियादी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी, तो ग्रामीण आखिर किस भरोसे सरकारी अस्पतालों का रुख करेंगे?

लोगों का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, आवश्यक उपकरणों और पर्याप्त व्यवस्थाओं का अभाव दिखाई देता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार प्रसव के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी मां और नवजात दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में अस्पताल से रेफर करने के बाद रास्ते में डिलीवरी होना गंभीर चिंता का विषय है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा और प्रसूताओं की जान जोखिम में पड़ती रहेगी।

जांच और कार्रवाई की उठी मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह भी मांग उठी है कि ढोढर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकों की तैनाती और प्रसव सेवाओं की वास्तविक स्थिति की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य गर्भवती महिला को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

यदि परिजनों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल एक अस्पताल की लापरवाही नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करने वाला मामला साबित हो सकता है।

थाना तेन्दुआ पुलिस द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2022 में फरार स्थाई वारंटी संजय रावत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया

शिवपुरी (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमति यांगचेन डोलकर भूटिया जी के द्वारा जिले में फरार स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, अतिरिक्?त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी एवं एसडीओपी अनुभाग कोलारस के मार्गदर्शन में दिनांक 20.07.2026 को दौराने कॉम्बिंग गस्त माननीय विशेष न्यायालय एमपीडीपीके एक्ट शिवपुरी के प्र.क्र. 16/2022 में जारी फरार स्थाई वारंटी संजय पुत्र विजय सिंह रावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम लालगढ थाना सिरसौद हाल निवासी लाल माटी दुबे नर्सरी के पास शिवपुरी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी (म.प्र.) पावर हाउस खरई के पास मिला जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि. नीतू सिंह धाकड़, प्र.आर. 493 गजेन्द्र सिंह सोलंकी, प्र.आर. 264 सुनील सिंह जाट की विशेष भूमिका रही ।7

थाना कोतवाली पुलिस व्दारा 03 बालकों के माधव चौक से गुम होने की सूचना पर गंभीरता व तत्परता से कार्यवाही करते हुये गुम हुये तीनों बालकों को महज 30 मिनट में तलाश कर रातौर तिराहे से सुरक्षित दस्तयाब किया एवं उनके माता पिता को सुपुर्द किया गया।...

शिवपुरी (निज संवाददाता)। फरियादी व्दारा थाने पर सूचना दी गयी कि उसके तीन नाबालिक बालक माधव चौक से कहीं गुम हो गये हैं, काफी तलाश करने पर नहीं मिल रहे हैं, सूचना की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित दुबे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी आर.डी. प्रजापति एवं एसडीओपी शिवपुरी श्री सचिन कुमार धुर्वे को सूचना से अवगत कराया वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा तीनों गुम बालकों को शीघ्रता से तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त पालन में थाना प्रभारी कोतवाली टीआई रोहित दुबे के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें गठित की गयी एवं बालकों की तलाश पुराना बस स्टेण्ड, माधव चौक, गुरुव्दारा चौराहा, न्यू ब्लॉक, झांसी चौराहा, गुना बायपास, फतेहपुर चौराहा पर की गयी जो गुम बालकों की तत्परता से तलाश कर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये रातौर तिराहे से महज 30 मिनट के अन्दर तीनों गुम बालकों को दस्तयाब कर उनके माता पिता के सुपुर्द किया गया अपने बालकों को वापस पाकर बालकों के पिता व परिवाजनों ने कोतवाली पुलिस की प्रशंसा कर आभार व्यक्त किया।

सराहनीय भूमिकाः- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली टीआई रोहित दुबे, उनि0 सुमित शर्मा, सउनि0 विवेक भट्ट, प्र.आर. 374 गजेन्द्र परिहार, प्र. आर. 86 भगवत चतुर्वेदी, आर. 285 राहुल कुमार, आर.चालक शरद यादव की विशेष भूमिका रही।

दुग्ध विक्रेता संघ शिवपुरी के एड राजकुमार शाक्य बने अध्यक्ष...

जिम्मेदारी लेते ही कहा दुग्ध व्यापारियों सहित जनता के हितों को लेकर रखा जाएगा ध्यान

शिवपुरी (निज संवाददाता)। जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित होटल मातोश्री परिसर में दुग्ध विक्रेता संघ शिवपुरी की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी दुग्ध व्यापारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए सर्वानुमति से युवा अधिवक्ता राजकुमार शाक्य को दुग्ध विक्रेता संघ शिवपुरी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मनोनयन के समय सभी दुग्ध व्यापारियों ने आशा व्यक्त की कि समय समय पर दुग्ध को लेकर आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी इन समस्याओं को लेकर अब दुग्ध व्यापारी संघ के द्वारा जनहित में अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस अवसर पर दुग्ध विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोनीत होने पर एड राजकुमार शाक्य ने सभी दुग्ध व्यापारियों के प्रति अपने इस मनोनयन पर आभार प्रकट किया और आश्वस्त किया कि दुग्ध व्यापारियों सहित आमजन के हितो को लेकर हमेशा ख्याल रखा जाएगा और यदि कानूनी आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए अधिकारों का प्रयोग करते ही माननीय न्यायालय की शरण लेने भी हम पीछे नहीं रहेंगे। इस अवसर पर सभी दुग्ध व्यापारियों के द्वारा एड राजकुमार शाक्य का मालार्पण करते हुए स्वागत सम्मान किया गया। इस मनोनयन के दौरान दुग्ध विक्रेता संघ शिवपुरी के आनंद राठौर, मुकेश जैन, दीपेश राठौर, धनीराम यादव, भूरा शिवहरे, आशाराम चौरसिया, हरि शर्मा, दीपक जैन, सुमत जैन, दीपेश राठौर, होतम बघेल, राकेश पाल, ललित पाराशर, उदयराज परिहार, मस्तराम यादव, अजय राठौर, रवि जैन, राजाराम धाकड़, मनोज राठौर सहित सैकड़ों की संख्या में दुग्ध विक्रेता मौजूद रहे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक में दिए सख्त निर्देश

दस्तक अभियान की नियमित निगरानी करें, शत प्रतिशत बच्चों को कवर किया जाए

शिवपुरी (निज संवाददाता)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अंतर-विभागीय समन्वय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, दस्तक अभियान, समय-सीमा के प्रकरणों तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने विशेष रूप से दस्तक अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि अभियान का प्रत्येक चरण पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में डायरिया और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ओआरएस, जिंक, आवश्यक दवाइयों और अन्य चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अभियान से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित फील्ड मॉनिटरिंग करने और प्रत्येक गतिविधि का समय पर सत्यापन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिले में 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर पाँच वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। बच्चों में डायरिया, कुपोषण, एनीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। गंभीर स्थिति वाले बच्चों को तत्काल उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पात्र परिवार को ओआरएस पैकेट, जिंक की गोलियां, आयरन सिरप तथा निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभियान केवल दवा वितरण तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने की आदत और दस्त होने पर ओआरएस एवं जिंक के सही उपयोग के बारे में भी जागरूक किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अभियान की सभी गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की भी विभागवार समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनशिकायतों एवं समय-सीमा के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी बनाए रखें।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय राज, एडीएम दिनेश शुक्ला सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

शिवपुरी में 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान तेज, 1000 स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली; फिजिकल थाना पुलिस ने स्कूल में दिलाई शपथ....

शिवपुरी (निज संवाददाता)। मध्यप्रदेश पुलिस के 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के तहत सोमवार को शिवपुरी शहर में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। कोतवाली पुलिस ने उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 के करीब एक हजार स्कूली बच्चों के साथ शहर में जनजागरूकता रैली निकाली। वहीं फिजिकल थाना पुलिस ने सैंड बेनेडिक्ट स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी और नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया।

कोतवाली पुलिस द्वारा आयोजित रैली की शुरुआत कोतवाली परिसर से हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामदास प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में शामिल स्कूली बच्चे हाथों में 'नशे से दूरी है जरूरी' लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चल रहे थे। इस दौरान डीजे पर नशा विरोधी जागरूकता गीत भी बजाए गए, जिससे लोगों का ध्यान अभियान की ओर आकर्षित हुआ।

रैली आर्य समाज मंदिर, मिर्ची बाजार, माधव चौक और कोर्ट रोड से होते हुए पोलो ग्राउंड पहुंची। यहां कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने विद्यार्थियों और उपस्थित नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई।

इधर, फिजिकल थाना पुलिस ने सैंड बेनेडिक्ट स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों व परिचितों को भी इस अभियान से जोड़कर नशामुक्त समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।

शिवपुरीः स्टोन क्रशर से फसलें हो रहीं बर्बाद, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लीज निरस्त करने की मांग की....

करैरा (शिवपुरी):(निज संवाददाता)। तहसील करैरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पारागढ़ और अमोपठा के किसानों ने गांव में संचालित स्टोन क्रशर (क्रेशर) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सोमवार को जिलाधिकारी (शिवपुरी) को ज्ञापन सौंपकर स्टोन क्रशर ठेकेदार पर गैर-कानूनी कार्य करने और फसलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

ब्लास्टिंग, धूल और मलबे से खड़ी फसलें हो रहीं चौपट

ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, ग्राम पारागढ़ स्थित भूमि सर्वे नंबर 355 पर खनिज विभाग से लीज लेकर स्टोन क्रशर का संचालन श्रीमती पूजा खटीक (पत्नी पवन खटीक) द्वारा किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि क्रशर के संचालन से भारी मात्रा में धूल, पत्थर और मलबा उनके खेतों में गिर रहा है। इसके साथ ही क्रशर पर होने वाली हैवी ब्लास्टिंग के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

कार्रवाई न होने से आक्रोशित हैं ग्रामीण

किसानों ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी अमोलपठा पुलिस चौकी पर शिकायत (धारा 174 भा.ना.सु.संहि 2023 के अंतर्गत अपराध धारा 324 (4) बी.एन.एस.) दर्ज कराई गई थी, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।

8 दिन का अल्टीमेटम, धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

ज्ञापन के माध्यम से समस्त पारागढ़ एवं अमोपठा निवासियों (कामता प्रसाद लोधी, पानसिंह, कोकसिंह, बाबूलाल, पंकज, जितेंद्र, निहाल आदि) ने मांग की है किः

तत्काल प्रभाव से इस मामले की जांच करवाई जाए।

फसलों के हुए नुकसान का सही आंकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।

नियमों के उल्लंघन पर भूमि सर्वे क्र. 355 पर संचालित स्टोन क्रशर की लीज निरस्त की जाए।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 8 दिनों के भीतर उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया, तो वे धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

संपादकीय

बलोचिस्तान में स्वघोषित आजादी

रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान के नाम से सोशल मीडिया पर एक स्वघोषित बयान और पत्र वायरल हुए हैं। इसमें बलोच नेता मीर यार बलोच और कुछ पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने बलोचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अपना नया झंडा और राष्ट्रगान जारी करते हुए सरकार बना लेने का दावा भी किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने 27 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर हत्या कर दी है। इससे बलोच आंदोलन उत्साहित हुआ है और वे जल्द कानूनी रूप में आजादी मिल जाने की उम्मीद करने लगे है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पाकिस्तान सेना ने बलोचिस्तान में फ्रंटियर कोर, पुलिस व आतंकवाद निरोधक बल के साथ ऑपरेशन शाबान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के सामने अब बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीएलए को इजराइली खुफिया एजेंसियों से धन, तकनीक और आधुनिक संचार उपकरण मिल रहे हैं। पाक सेना ने लड़ाकों के पास से स्टारलिंग उपकरण जब्त किए हैं।

विद्रोही बलोचों ने करीब 85 प्रतिशत बलोचिस्तान की भूमि पर काबिज होने का दावा किया है। बलोच कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील भी कर दी है। यह पाकिस्तान का वह प्रमुख क्षेत्र है, जहां से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजर रहा है। इसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यही वह क्षेत्र है, जहां अत्यंत दुर्लभ खनिज एवं प्राकृतिक गैसें उपलब्ध हैं। यही पाकिस्तान की अर्थव्यस्था की रीढ़ हैं। बलोचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है, वह अब सफलता के शिखर पर है। बलोचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। अब बलोच भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलोचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलोचिस्तान के लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए जाने जाते हैं। बलोचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाक सेना को बलोच सीमा क्षेत्र से बाहर कर देने का आग्रह भी किया है। यदि बलोच स्वतंत्र देश बन जाता है तो भारत-पाक युद्ध के बीच 1971 की तरह एक युगांतरकारी घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलोचों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में भारत भी भागीदार हो सकता है। बलोचों की स्वतंत्रता की संभावना का अहसास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जताया है। उनका कहना है कि बलोचिस्तान पर अब सेना और सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। यहां के हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बाहरी सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। सेना के जवान अपने ही देश में बंकरों में छिपे हैं। बलोचिस्तान में विद्रोह की आग चरम पर है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलोचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद किया था। कालांतर में सैनिक तानाशाह जिया उल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलोच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलोचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलोचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलोच नेता खेरबक्ष मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलोचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई। बीएलए बलोचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलोचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलोचिस्तान में बलोचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। अतैव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलोचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी, जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलोचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसीलिए वे बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तभी से यह संगठन पाक सेना से लोहा ले रहा है। वर्तमान में बलोच अलगाववादी और तालिबान के बीच निरंतर निकटता बढ़ रही है। वैसे भी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाक सरकार ने भी स्वीकार किया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ही बलोच लड़ाकों को प्रशिक्षित कर रहा है। बलोचिस्तान प्रांत में अब महिलाओं ने भी बीएलए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलूच नागरिकों के दमन चक्र के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया है। इस सच्चाई को पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी स्वीकारा है।

पाकिस्तान की आजादी के साथ बलोचिस्तान का मुद्दा जुड़ा है। पाक की कुल भूमि का 43.6 फीसदी हिस्सा केवल बलोचिस्तान का है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलोच हैं, पाक की कुल आबादी में इनकी छह प्रतिशत की भागीदारी है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किमी है। यहां हिंदू, सिख और ईसाई भी रहते हैं। इनमें आपस में खूब भाईचारा है। भगवान शिव की पत्नी सती का हिंगलाज मंदिर इसी बलोच क्षेत्र में आता है। अनेक मुसलमान भी देवी सती की पूजा-अर्चना करते हैं, क्योंकि ये धर्मांतरित है। यहां से कभी सांप्रदायिक दंगों की खबरें नहीं आती हैं। 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलोच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलोचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। पीओके और बलोचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह, जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण देता रहा है, वहीं बलोचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है। यहां सोना, तांबा, कोयला और प्राकृतिक गैसों के बड़े भंडार है, लेकिन इनसे कमाई का बड़ा हिस्सा पाक सरकार, सेना और चीनी कंपनियां हथिया लेती हैं। इस कारण लोगों का गुस्सा उबाल पर है। बलोचिस्तान की कलात रियासत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल हो गई थी। लेकिन बलोचिस्तान ने पाक में विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। लिहाजा यहां अलगाव की आग निरंतर बनी रही है। नतीजतन 2001 में यहां 50 हजार लोगों की हत्या पाक सेना ने कर दी थी। इसके बाद 2006 में अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले 20 हजार सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया गया था, जिनका आज तक पता नहीं है। 2015 में 157 लोगों के अंग-भंग किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने जाने-माने एक्टिविस्ट बाबा जान को भी हिरासत में लिया हुआ है। पिछले 20 साल से जारी दमन की इस सूची का खुलासा एक अमेरिकी संस्था ने किया है। वाशिंगटन में कार्यरत संस्था गिलगित-बलोचिस्तान नेशनल कांग्रेस के सेंग सिरिंग ने मोदी द्वारा उठाए, इस सवाल का समर्थन किया है कि 'पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलोचिस्तान में लोगों पर होने वाले जुल्म एवं अत्याचार के बाबत पाक को दुनिया के समक्ष जवाब देना होगा ? पाक तो जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह बलोचिस्तान की स्वतंत्रता में भागीदार बने?

प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी : आज के समय में प्रासंगिकता और नई शिक्षा की दिशा

— डॉ. भूपेंद्र कुमार सुल्लेरे

'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। '

अर्थात् ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। भारत की वैज्ञानिक परंपरा इसी ज्ञान-दृष्टि पर आधारित रही है, जहाँ विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन, प्रकृति, समाज और नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ था। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ढ्ढ), जनरेटिव तकनीक, रोबोटिक्स, 5त्र, ड्रोन, अंतरिक्ष विज्ञान, 3डी प्रिंटिंग और जैव प्रौद्योगिकी का युग है, तब प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विरासत को समझना और उसे आधुनिक शिक्षा से जोड़ना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है।

प्राचीन भारत का वैज्ञानिक और तकनीकी अतीत केवल इतिहास का गौरवशाली अध्याय नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक भी है। सिंधु-सरस्वती (सिंधु घाटी) सभ्यता से लेकर वैदिक काल, महाजनपद युग और गुप्तकाल तक भारत ने गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, वास्तुकला और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में ऐसी उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, जिनका प्रभाव आज भी वैश्विक विज्ञान पर स्पष्ट दिखाई देता है। यह विरासत इस बात का प्रमाण है कि भारतीय चिंतन केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं था, बल्कि मानव जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने पर आधारित था।

लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित सिंधु घाटी सभ्यता में सुनियोजित नगर, चौड़ी सड़कें, भूमिगत जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत ईंटें, जल प्रबंधन और उत्कृष्ट धातु शिल्प का विकास हुआ। उस समय जब विश्व के अनेक भाग प्रारंभिक सभ्यता के चरण में थे, भारत में सुव्यवस्थित शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया जा चुका था। वैदिक काल में कृषि विज्ञान, धातु विज्ञान, खगोलीय अवलोकन तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और विकसित किया।

भारत के तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व के प्रथम बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र थे। यहाँ दर्शन, गणित, चिकित्सा, व्याकरण, राजनीति, अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान और शिल्पकला का समन्वित अध्ययन होता था। आज जिस बहुविषयक शिक्षा (Multidisciplinary Education) की चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की जा रही है, उसकी जड़ें भारत की इसी प्राचीन ज्ञान परंपरा में निहित हैं।

भारतीय गणितज्ञों ने विश्व गणित को नई दिशा प्रदान की। आर्यभट ने आर्यभटीय में पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसकी परिधि का अत्यंत सटीक अनुमान लगाया। उन्होंने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र विकसित किए। ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियम स्थापित किए, जबकि भास्कराचार्य की लीलावती और बीजगणित ने गणितीय चिंतन को नई ऊँचाई प्रदान की। वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका और सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की गति, ग्रहण तथा खगोलीय गणनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज इसरो की मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान जैसी उपलब्धियाँ उसी वैज्ञानिक परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान विश्व के लिए अमूल्य है। चरक संहिता में कहा गया है– 'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, आतुरस्य विकार प्रशमनम्।' अर्थात् स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का उपचार करना चिकित्सा का उद्देश्य है। चरक संहिता शरीर, मन, आहार और जीवनशैली के संतुलन पर बल देती है, जबकि सुश्रुत संहिता विश्व का सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा ग्रंथ मानी जाती है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन तथा अनेक जटिल शल्य प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज जब मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और हृदय रोग जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, तब आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, संतुलित आहार और प्राकृतिक जीवनशैली पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। पतंजलि योगसूत्र का प्रसिद्ध सूत्र– 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' –योग को मन की चंचल वृत्तियों पर नियंत्रण का माध्यम बताता है। योग के आठ अंग–यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि–व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का समग्र मार्ग प्रस्तुत करते हैं। आज तनाव, अवसाद, डिजिटल व्यसन और परीक्षा के दबाव से जूझती युवा पीढ़ी के लिए योग और ध्यान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद विश्वभर में योग की स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है।

धातु विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ भी अद्वितीय हैं। दिल्ली का लगभग 1600 वर्ष पुराना जंगरहित लौह स्तंभ आज भी वैज्ञानिकों और धातु विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। नागार्जुन के रसशास्त्र में धातुओं, खनिजों और औषधियों के वैज्ञानिक उपयोग का उल्लेख मिलता है। भारतीय इस्पात निर्माण और मिश्र धातुओं का ज्ञान उस समय विश्व में अग्रणी माना जाता था।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी भारतीय परंपरा अत्यंत वैज्ञानिक रही है। अथर्ववेद का मंत्र– 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' –पृथ्वी को माता और मनुष्य को उसका पुत्र मानते हुए प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। पीपल, नीम और वट जैसे वृक्षों की पूजा, वर्षा जल संचयन, तालाबों का निर्माण, मिश्रित खेती, जैविक खाद और वन संरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ आज के सतत विकास (स्ह्वह्यह्लड्डद्बठ्ठड्डद्यद्ग ष्ठद्ग1द्गद्यश्चद्वद्गठ्ठह्ल) के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती हैं। जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, तब भारतीय पारंपरिक ज्ञान नए समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

वास्तु शास्त्र भी केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भवन निर्माण का अनुशासन है। इसमें सूर्य के प्रकाश, वायु प्रवाह, ताप नियंत्रण, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग, पैसिव कूलिंग, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था और ऊर्जा संरक्षण की अवधारणाएँ वास्तु के अनेक सिद्धांतों से साम्य रखती हैं।

आज भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश कर चुका है। किंतु तकनीकी प्रगति के साथ-साथ मानसिक तनाव, नैतिक संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और जीवनशैली संबंधी रोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें यह सिखाती है कि विज्ञान केवल तकनीकी विकास का साधन नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम भी होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्त्रश्वरू) शिक्षा के साथ जोड़ने का स्पष्ट आह्वान किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, भारतीय वैज्ञानिक विरासत के प्रति सम्मान उत्पन्न करना तथा नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यदि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आर्यभट, चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, नागार्जुन तथा भारतीय वास्तु, आयुर्वेद और पर्यावरणीय ज्ञान का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भों के साथ कराया जाए, तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुसंधान क्षमता और नवाचार की भावना और अधिक विकसित होगी।

यह आवश्यक है कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को न तो अंधभक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाए और न ही उन्हें केवल मिथक मानकर उपेक्षित किया जाए। वैज्ञानिक प्रमाणों, ऐतिहासिक तथ्यों और आधुनिक अनुसंधान के आधार पर इन उपलब्धियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता मिलेगी कि विज्ञान किसी एक देश या सभ्यता की संपत्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का साझा बौद्धिक प्रयास है, जिसमें भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। यही समन्वय भारत को ज्ञान-आधारित, आत्मनिर्भर, नवाचार-संपन्न और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करेगा। भारत की वैज्ञानिक विरासत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। यदि इसे शिक्षा, अनुसंधान और नीति-निर्माण का अभिन्न अंग बनाया जाए, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता और सतत विकास का मजबूत आधार सिद्ध होगी।

भारतीय मजदूर संघ : श्रमिक चेतना का राष्ट्रवादी अध्याय

श्रम का राष्ट्रीयकरण करें, उद्योग का श्रमिकीकरण करें और राष्ट्र का औद्योगीकरण करें।-दत्तोपंत ठेंगड़ी

विपिन बिहारी पाठक

यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के श्रम-दर्शन का सार है। उन्होंने भारतीय श्रमिक आंदोलन को वर्ग संघर्ष की संकीर्ण सोच से निकालकर राष्ट्रनिर्माण की व्यापक अवधारणा से जोड़ा। यही कारण है कि आज भी भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) केवल एक ट्रेड यूनियन नहीं, बल्कि राष्ट्रहित, श्रमिकहित और उद्योगहित के संतुलन का एक विशिष्ट मॉडल माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत वैचारिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। विश्व का बड़ा हिस्सा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था और भारतीय श्रमिक आंदोलन पर भी वामपंथी संगठनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। उस समय श्रमिक आंदोलनों में 'वर्ग संघर्ष' की अवधारणा प्रमुख थी। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस सोच को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं माना। उनका विश्वास था कि श्रमिक, उद्योग और समाज एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही राष्ट्रीय परिवार के पूरक अंग हैं। इसलिए संघर्ष नहीं, सहयोग ही स्थायी विकास का मार्ग हो सकता है।

इसी विचार को व्यवहार में उतारने के लिए 23 जुलाई 1955 को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के दिन, भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत अत्यंत साधारण परिस्थितियों में हुई। न कोई बड़ा संगठन, न सदस्यता, न कार्यालय और न ही आर्थिक संसाधन। केवल 35 कार्यकर्ताओं के साथ प्रारंभ हुआ यह प्रयास आज देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठनों में गिना जाता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी में हुआ। छात्र जीवन से ही उनमें राष्ट्र और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। आगे चलकर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने और संगठन निर्माण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय मजदूर संघ के अतिरिक्त उन्होंने भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और सामाजिक समरसता मंच जैसे अनेक संगठनों की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि उन्हें पद्मभूषण सम्मान की घोषणा भी हुई, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

ठेंगड़ी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने श्रमिक आंदोलन को राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा से अलग रखने का प्रयास किया। उनका मानना था कि ट्रेड यूनियन का मूल उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि किसी राजनीतिक दल का विस्तार बनना। यही कारण है कि भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को दलगत राजनीति से अलग रखते हुए श्रमिकों के संगठन के रूप में विकसित किया।

बीएमएस की वैचारिक पृष्ठभूमि भारतीय संस्कृति और 'एकात्म मानववाद' पर आधारित है। यह मानती है कि जीवन में विविधता अवश्य है, किंतु उसके मूल में एकता निहित है। इसलिए श्रमिक और उद्योगपति परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा के सहभागी हैं। यदि दोनों के बीच विश्वास और सहयोग का वातावरण बने तो उत्पादन भी बढ़ेगा और श्रमिकों का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। इसी सोच से प्रेरित होकर दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 'अधिकतम उत्पादन और समान वितरण' का सिद्धांत दिया। उन्होंने पूंजीवाद की केवल उत्पादन-केंद्रित सोच और समाजवाद की केवल वितरण-केंद्रित सोच के स्थान पर संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि अधिक उत्पादन राष्ट्र का कर्तव्य है और उत्पादन के लाभ का न्यायपूर्ण वितरण श्रमिक का अधिकार।

भारतीय मजदूर संघ का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य– 'हम राष्ट्रहित में काम करेंगे और पूर्ण वेतन की मांग करेंगे '–आज भी श्रम और राष्ट्र के बीच संतुलन का संदेश देता है। यह नारा बताता है कि श्रमिक का संघर्ष केवल अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि के लिए भी होना चाहिए।

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादी नारों की भी नई परंपरा विकसित की। उन्होंने उस दौर के अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी नारों के स्थान पर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विचार प्रस्तुत किए। 'श्रम का राष्ट्रीयकरण, उद्योग का श्रमिकीकरण और राष्ट्र का औद्योगीकरण' का उनका संदेश श्रमिक को केवल मजदूर नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माता के रूप में स्थापित करता है। बीएमएस ने 'औद्योगिक परिवार' की अवधारणा भी दी, जिसमें श्रमिक, प्रबंधन और समाज तीनों को विकास की साझी इकाई माना गया।

ठेंगड़ी जी ने स्व-रोजगार और पारंपरिक कारीगरों के महत्व को भी समय रहते पहचान लिया था। उन्होंने सुनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, धोबी जैसे पारंपरिक व्यवसायों को 'विश्वकर्मा क्षेत्र' की संज्ञा दी और इसे जनता का क्षेत्र बताया। यह दृष्टि आज 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' और कौशल विकास जैसे अभियानों के संदर्भ में और भी प्रासंगिक प्रतीत होती है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी केवल संगठनकर्ता ही नहीं, बल्कि गंभीर चिंतक और विपुल लेखक भी थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी में अनेक पुस्तकों के माध्यम से श्रम, अर्थनीति, स्वदेशी और राष्ट्रवाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण आवश्यक है, परंतु उसका अर्थ पश्चिमीकरण नहीं हो सकता। विकास का भारतीय मॉडल भारतीय समाज, संस्कृति और परिस्थितियों के अनुरूप ही होना चाहिए।

आज भारतीय मजदूर संघ देशभर में हजारों संबद्ध यूनियनों और व्यापक सदस्य आधार के साथ श्रमिक हितों की आवाज़ बन चुका है। समय-समय पर उसने विभिन्न सरकारों की उन नीतियों का भी विरोध किया जिन्हें उसने श्रमिक हितों के प्रतिकूल माना।

'जिधर देखो...'

जिधर देखो, मौन खड़े हैं,
प्रश्न सभी अब कौन करे?
सच की चौखट सूनी-सूनी,
झूठ यहाँ सिंहासन धरे।

योग्यता का दीप बुझाकर,
चाटुकारों का मेला है,
मेहनत, प्रतिभा, ज्ञान भटकते,
सत्ता का बस खेला है।

जो सिर झुकाए, वही पुरस्कृत,
जो सच बोले, दंड मिले,
विवेक यहाँ निर्वासन झेले,
स्वार्थों के ही छंद मिले।

कठपुतलियों की भीड़ सजी है,
डोर किसी के हाथ रही,
जनहित पीछे छूट गया है,
कुर्सी सबसे साथ रही।

कब तक यूँ ही मौन रहेंगे?
कब तक झुककर जीना है?
सत्य, न्याय और योग्यता को,
फिर से मिलकर सीना है।

जिधर देखो विवेक जगे तो,
बदलेगा यह दौर सभी;
योग्यता का मान रहेगा,
तभी बचेगा देश अभी।

डॉ भूपेन्द्र कुमार

ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग के विरोध में स्वास्थ्य कर्मी 22 को निकालेंगे रैली करेंगे प्रर्दशन

जगदलपुर,20 जुलाई (हिस)।स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार के ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग निर्णय के विरोध में आंदोलन का एलान कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों की लैब संचालन व्यवस्था केरल की एचएलएल कंपनी को ठेका में सौंपने का फैसला किया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने 22 जुलाई को रैली निकालकर प्रर्दशन करने का ज्ञापन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया है।

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बीजापुर के जिलाध्यक्ष सदाशिव दुर्गम ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों का मूल उद्देश्य जनसेवा होता है। निजी कंपनियां केवल व्यवसाय और लाभ कमाने के लिए कार्य करती हैं। उन्होने सवाल उठाया कि निजी कंपनियों पर जिला प्रशासन का नियंत्रण कितना प्रभावी होगा। सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होते हैं। लापरवाही पर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

उन्होने आशंका जताई कि लैब संचालन के बाद फार्मेसी सेवाओं को भी निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो पैरामेडिकल और फार्मेसी क्षेत्र में रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। संघ का कहना है कि इस निर्णय से वर्तमान कर्मचारियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्तियों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी दी है। यदि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे वापस नहीं लेती है। तो आने वाले समय में प्रदेशभर के स्वास्थ्य कर्मचारी व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

चार पंचायतों ने खोला मोर्चा, सोरम की शराब दुकान हटाने कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंच

धमतरी, 20 जुलाई (हि.स.)। स्कूल, आइटीआइ और अस्पताल के समीप संचालित सोरम की शराब दुकान के विरोध में चार ग्राम पंचायतों ने मोर्चा खोल दिया है। भटगांव, बेंद्रानवागांव, रूद्री और श्यामतराई ग्राम पंचायत के सरपंच सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने मांग की है।

जिला सरपंच संघ उपाध्यक्ष एवं भटगांव सरपंच फागू राम साहू, बेंद्रानवागांव सरपंच प्रसून शुक्ला और रुद्री सरपंच लक्ष्मी बया ने बताया कि सोरम स्थित शराब दुकान से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आइटीआइ कालेज और 400 मीटर की दूरी पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। वहीं समीप ही अस्पताल भी है। शराब सेवन करने वालों की आवाजाही और नशे की हालत में किए जाने वाले उत्पात से छात्र-छात्राओं, विशेषकर छोटे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके स्वजन को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि शराब दुकान तक पहुंचने वाली सड़क संकरी और जर्जर है। शराब खरीदने आने वाले लोग सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। वहीं नशे की हालत में वाहन चलाने से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। सरपंचों ने कहा कि शराब दुकान खुलने के बाद क्षेत्र का सामाजिक माहौल भी बिगड़ा है। उन्होंने नाबालिग बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि समय रहते शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया गया तो इसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से बच्चों के भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए सोरम स्थित शराब दुकान को शीघ्र अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की।

चारामा में 5.96 लाख नगद के साथ 12 जुआरी पकड़ाये

कांकेर, 20 जुलाई (हि.स.)। जिले के चारामा थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों को आज सोमवार को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 31,510 रुपये नकद, 2 कार, 3 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल फोन, ताश के 52 पत्ते और एक चटाई सहित कुल पांच लाख 96 हजार 510 रुपये जब्त किया गया है। आरोपितों में अशिवदत्त निषाद, देवेंद्र कुमार सेन, खेमलाल गजेंद्र, वीरेंद्र मेश्राम, देवप्रसाद उईके, इंद्रजीत रामटेके, ईश्वर नेताम, प्रकाश सिन्हा, डी.के. बंछोर, गोविंद जुर्री, महेंद्र निषाद और अरुण मंडावी शामिल है। चारामा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीएचसी चारामा के समीप बने शेड में कुछ लोग ताश के पत्तों से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं।

‘मनिया में कृषि विभाग का छापा स्टॉक में गड़बड़ी पर तीन खाद बीज दुकानों के लाइसेंस निलंबित

धौलपुर (निज संवाददाता)। किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की टीम द्वारा शनिवार को पंचायत समिति मनिया क्षेत्र में कृषि आदान विक्रेताओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार प्रभु दयाल शर्मा के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों ने मैसर्स बालाजी खाद बीज भंडार दीनानाथ खाद बीज भंडार एवं आरजी खाद बीज भंडार का विक्रय केन्द्र एवं गोदाम का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर पीओएस मशीन में दर्ज विवरण तथा मौके पर उपलब्ध यूरिया उर्वरक के भौतिक सत्यापन का मिलान किया गया। जांच के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों में अभिलेखों एवं वास्तविक स्टॉक के बीच भिन्नता पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितता मानते हुए मैसर्स बालाजी खाद बीज भंडार दीनानाथ खाद बीज भंडार एवं आर.जी. खाद बीज भंडार के उर्वरक अनुज्ञा पत्रों को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उर्वरकों की कालाबाजारी स्टॉक में अनियमितता तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है तथा दोषी पाए जाने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल में कृषि अधिकारी गिरिराज माहुर कैलाश चन्द शर्मा सहायक कृषि अधिकारी शुभम एवं जगदीश रावत कृषि पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार सोनवीर तथा रघुनाथ उपस्थित रहे।

जोखिम भरे पुलिया एवं रपटों पर आमजन की आवाजाही पर प्रभावी तरीके से लगाएं रोक-अतिरिक्त जिला कलक्टर

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के सम्बन्ध में दिए निर्देश

धौलपुर (निज संवाददाता)। अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना ने कहा कि मानसून को देखते हुए जोखिम भरे पुलिया रपटों पर आमजन की आवाजाही पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाएं। अतिरिक्त जिला कलक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार मे साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को जिले मे सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति रखने, आमजन की विद्युत संबंधी समस्याओं का समय सीमा में निस्तारण करने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सभी विभाग लक्ष्यानुसार पौधारोपण कर मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएमएचओ को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार हेतु तैयारियां किए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के संबंध मे सतर्क व सक्रिय रहकर कार्य करते हुए विभागीय कार्मिकों द्वारा व्यापक रूप से एंटी लार्वा गतिविधियां संपादित करवाएं। साथ ही नगर परिषद जल भराव क्षेत्रों में फॉगिंग कराया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने पीएचईडी को पेयजल की समय समय पर गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं प्रतिदिन जनसुनवाई में प्राप्त लंबित परिवादों की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। साथ ही न्यूज पेपर कटिंग्स पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों को अत्यंत संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता से लेते हुए त्वरित एवं तर्कसंगत समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

पेपर लीक के विरोध में आगरा में उबाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

आगरा (निज संवाददाता)। देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में पिछले 22 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे महान समाजसेवी सोनम वांगचुक एवं आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में सोमवार को आगरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती एवं परीक्षा व्यवस्था की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने माननीय राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

इस दौरान समाजसेवी डॉ. हृदेश चौधरी ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। वर्षों की मेहनत करने वाले छात्र बार-बार भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। यह केवल परीक्षाओं का नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास और देश के भविष्य का प्रश्न है।

समाजसेवी सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी और दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक युवाओं के साथ न्याय संभव नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानून लागू करने की अपील की।

प्रदर्शनकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और आंदोलनरत छात्रों की मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए ताकि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।

प्रदर्शन के अंत में सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक में चंद्रावती नरवार , प्रमोद शर्मा, लेखराज निगम, डॉ श्वेता अग्रवाल, गुलबीर सिंह पौनीया, मोहित अग्रवाल, ताजुद्दीन खान, संजय भारती, अरुण प्रताप गहलोत, अभिनीत सिंह, प्रथम दीक्षित, हर्ष कुमार सिंह, विजय आनंद, पंकज चावला, इंद्र कुमार वर्मा, आशीष कपूर, शैलेंद्र गायत्री, कृष्ण गोपाल उपाध्याय, विष्णु कुशवाहा, प्रवीण सिंह आदि सैकड़ो साथी मौजूद रहे ।

पारिवारिक विवाद में बिछड़े बुजुर्ग की सरमथुरा पुलिस ने कराई घर वापसी एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर हुई काउंसलिंग

धौलपुर (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं मानवीय समाधान की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सरमथुरा थाना पुलिस ने एक सराहनीय एवं संवेदनशील पहल करते हुए पारिवारिक विवाद के कारण अपने परिवार से अलग रह रहे एक बुजुर्ग को पुनः उनके परिवार से मिलाकर घर वापसी कराई। ग्राम कोनेसा निवासी बुजुर्ग श्री नथुआ राम मीना, जो तीन पुत्रों के पिता हैं, पारिवारिक अनबन के चलते पिछले कुछ समय से अपने परिवार से अलग रह रहे थे। विगत दिनों उन्होंने पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अपनी पीड़ा एवं पारिवारिक समस्या से अवगत कराया था। बुजुर्ग की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने तत्काल थानाधिकारी सरमथुरा को आवश्यक कार्रवाई कर पारिवारिक स्तर पर समाधान कराने के निर्देश दिए। निर्देशों की पालना में सरमथुरा थाना पुलिस ने बुजुर्ग श्री नथुआ राम मीना के पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों को थाने बुलाकर उनकी काउंसलिंग की। पुलिस अधिकारियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बुजुर्गों के सम्मान उनके अधिकारों तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए आपसी संवाद एवं समझाइश के माध्यम से विवाद का समाधान कराया। काउंसलिंग के उपरांत परिजनों द्वारा पिता की पूरी देखभाल करने, उनका सम्मान बनाए रखने तथा भविष्य में किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं होने देने का पुलिस के समक्ष पूर्ण आश्वासन दिया। इसके बाद बुजुर्ग श्री नथुआ राम मीना की सम्मानपूर्वक उनके परिवार में घर वापसी कराई गई। लंबे समय बाद परिवार का साथ

मिलने पर बुजुर्ग श्री नथुआ राम मीना के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने धौलपुर पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की संवेदनशील पहल से उन्हें दोबारा अपने परिवार का स्नेह और सहारा मिल सका। धौलपुर पुलिस का मानना है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर, असहाय एवं वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भविष्य में भी धौलपुर पुलिस आमजन, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए इसी प्रकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करती रहेगी।

आगरा मंडल में 01 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक बिना उचित कारण अलार्म चेन खीचने (ACP) वाले 123 लोंगो पर कार्यवाही

आगरा (निज संवाददाता)।मंडल रेल प्रबंधक आगरा श्री गगन गोयल के दिशा निर्देशन में आगरा मंडल में 01 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 बिना उचित कारण अलार्म चेन खीचने (ACP) वाले 123 लोंगो पर कार्यवाही करके 88,865/- रूपये जुर्माना वसूला गया । आगरा मण्डल सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है7 इस अभियान के अंतर्गत आगरा मंडल के विभिन्न रेल खंडों, प्रमुख स्टेशनों एवं ट्रेनों में नियमित रूप से सघन जांच, निगरानी एवं जागरूकता गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ट्रेनों के समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन को बनाए रखा जा सके। अलार्म चैन पुलिंग का स्टेशनो पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है और बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि अनावश्यक चैन पुलिंग ना करे RDN स्क्रीन के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना उचित एवं प्रर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है । उक्त कृत्य से आपके साथी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता ह।

थोड़ी-सी बारिश में डूबा धौलपुर जलभराव के बीच खुले नाले में समाई बाइक लोगों ने बचाई

धौलपुर (निज संवाददाता)। शहर में हुई थोड़ी-सी बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कें तालाब जैसी दिखाई देने लगीं, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गईं। इसी दौरान सड़क किनारे बने एक खुले नाले में एक बाइक अचानक गिर गई। घटना होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर स्थिति संभाली और कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को सुरक्षित नाले से बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जलभराव के कारण सड़क और नाले का अंतर

दिखाई नहीं देता जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि शहर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने और कई स्थानों पर खुले नालों पर सुरक्षा इंतजाम न होने से हर बारिश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों की तत्काल पहचान कर प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था की जाए। साथ ही खुले नालों को ढकने चेतावनी संकेत लगाने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और आमजन सुरक्षित रह सकें।

आगरा में 22 जुलाई से 8 सितंबर तक चलेगा नि:शुल्क खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान, 6.22 लाख पशुओं को लगेगा टीका

एफएमडी नियंत्रण को लेकर आगरा में विशेष अभियान शुरू, 49 टीमें घर-घर जाकर करेंगी पशुओं का टीकाकरण मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की पशुपालकों से अपील—खुरपका-मुंहपका से बचाव के लिए जरूर लगवाएं नि:शुल्क टीका

आगरा (निज संवाददाता) । मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. डी.के. पाण्डेय ने अवगत कराया है कि पशुओं में होने वाले खुरपका-मुँहपका रोग के नियन्त्रण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एफ0एम0डी0सी0पी0 योजना के तहत अष्टम चरण में पशुओं में टीकाकरण कार्य जनपद में दिनांक 22.07.2026 से 08.09.2026 तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान जनपद के 622150 गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का नि:शुल्क टीकाकरण किया जायेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद के सभी 15 विकास खण्डों में स्थित सभी पशु चिकित्सालयों के माध्यम से टीकाकरण सम्पादित किया जायेगा। इसके लिए 49 टीकाकरण टीमें गठित की गयी है। जो गाँव-गाँव और घर-घर पहुँचकर पशुओं को नि:शुल्क टीका लगायेगी। 04 माह से कम आयु के बच्चों तथा 08 माह से अधिक गर्भित गाय एवं भैसों को छोडकर सभी पात्र पशुओं को टीकाकरण किया जायेगा।

उन्होंने जनपद के समस्त पशुपालकों से अपील की है कि वह अपने गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में टीकाकरण कार्य करायें एवं इस भयंकर बीमारी की रोकथाम में अपना सहयोग प्रदान करें। जनपद के सभी ग्राम प्रधानों / अन्य जनप्रतिनिधियों से भी अपील की जाती है कि पशुपालन विभाग की ग्राम में जा रही टीकाकरण हेतु टीमों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी हेतु जनपद के समस्त पशुपालक अपने-अपने क्षेत्र के निकटस्थ पशुचिकित्सालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते है ।

पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की होगी जमीनी पड़ताल, कागजों तक नहीं रहेगा सीमित- जयवीर सिंह

जनहित के कार्यों में दिखना चाहिए जनता के धन का सदुपयोग- जयवीर सिंह

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शुरू की 18 मंडलों में समीक्षा बैठक, आगरा की 58 परियोजनाओं से शुरुआत

मंत्री जयवीर सिंह ने की कार्य योजना एवं निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा, विलंबित कार्य नवंबर तक पूर्ण करने के सख्त निर्देश

आगरा सहित अलीगढ़ में 500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों की समीक्षा, जनहित और पारदर्शिता होगी सबसे बड़ी कसौटी/अधिकारियों को सख्त निर्देश, जनप्रतिनिधियों के साथ स्थापित करें समन्वय

आगरा (निज संवाददाता)। मा. मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग श्री जयवीर सिंह जी की अध्यक्षता में एवं मा.जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ.मंजू भदौरिया जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाह जी,मा. विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह जी, डॉ. जीएस धर्मेश जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री भगवान सिंह जी, लोकदल जिलाध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना में सम्मिलित पर्यटन विभाग, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण, मा.जनप्रतिनिधिगण द्वारा दिये गए कार्यों के प्रस्ताव आदि संबंधी सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मा.मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास की योजनाएं अब केवल कागजी प्रस्तावों के आधार पर मंजूर नहीं होंगी। हर परियोजना का पहले जमीनी सत्यापन होगा। उसकी उपयोगिता और जनहित का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही योजनाओं को अंतिम स्वीकृति मिलेगी, ताकि जनता का पैसा वहीं खर्च हो, जहां उसका वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग, तीर्थ विकास परिषद की कार्ययोजना की प्रदेशव्यापी समीक्षा का शुभारंभ किया गया है। पहले चरण में आगरा और अलीगढ़ मंडल की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी ने बताया कि विशेष समीक्षा अभियान के पहले चरण में दोनों मंडलों (आगरा और अलीगढ़) की 80 परियोजनाओं का बिंदुवार निरीक्षण किया। प्रत्येक प्रस्ताव की प्रगति, गुणवत्ता और उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया। अब यही प्रक्रिया प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अपनाई जाएगी। प्रत्येक मंडल में समीक्षा बैठक के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा।

मंडलवार परियोजनाओं की समीक्षा : बैठक में आगरा मंडल की 58 पर्यटन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 273 करोड़ रुपए है। साथ ही, मथुरा की धर्मार्थ विभाग से संबंधित तीन परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसकी अनुमानित लागत करीब 245 करोड़ रुपए है।

'भाजपा गाय को भूल गई, राज्यमाता का दर्जा दो वरना होगा बड़ा आंदोलन' - डॉ.नागाजी सरकार '1008 '

बानमौर वांणगंगा स्थित नागाजी पीठ में पूज्य नागाजी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा गाय के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता मिलते ही गाय को भूल गई।

महाराज ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में अवैध कत्लखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं और रोजाना हजारों गायों का कत्ल हो रहा है। सरकार गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में सभी अवैध कत्लखाने तुरंत बंद किए जाएं और गौ तस्करी पर सख्त कानून बनाया जाए नागाजी सरकार ने धार्मिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, तो फिर केवल मंदिरों को ही सरकारी दायरे में क्यों रखा जा रहा है? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान हुई करोड़ों की चोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 'जहां भी ट्रस्ट बनता है वहां भ्रष्टाचार और लूट होती है उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि गाय को 'राज्य माता का दर्जा' दिया जाए और इसे राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ गौशालाओं के लिए पर्याप्त बजट भी दिया जाए महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने 2 महीने में गौ रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो संत समाज एकजुट होकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। इस आंदोलन की रूपरेखा जल्द तय की जाएगी। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में साधु-संत और स्थानीय श्रद्धालु मौजूद थे।

केंद्रीय विद्यालय में सुविधाओं के विस्तार को मिली मंजूरी, चिल्ड्रन पार्क, नया वाटर पॉइंट, कंप्यूटर और फर्नीचर होंगे उपलब्ध

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विद्यालय के समग्र विकास, आधुनिक संसाधनों के विस्तार तथा विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शैक्षणिक वातावरण तैयार करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य, डिप्टी कलेक्टर पवन घुरैया, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पवन सिंह मीणा सहित प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों के मनोरंजन एवं शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर में आधुनिक चिल्ड्रन पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए नया वाटर पॉइंट स्थापित किया जाएगा, जिससे बच्चों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके। विद्यालय में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए कंप्यूटर खरीदे जाने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ हो रहे कक्षा 10-बी के नए सेक्शन के लिए आवश्यक फर्नीचर की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक के बाद अधिकारियों ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर इनोवेशन एवं स्किल सेंटर सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में संचालित नवाचारों, आधुनिक शिक्षण व्यवस्थाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी भी प्राप्त की गई।

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या और आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाए, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक संसाधनों का लाभ भी विद्यार्थियों को मिल सके। विद्यालय प्रबंधन समिति ने भविष्य में भी आवश्यकतानुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की।

विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मिले भाजपा चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह

बैठक में भाजपा की नीतियों पर चर्चा, कांग्रेस पर लगाए राजनीतिक आरोप

दतिया (निज संवाददाता)। दतिया विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने सोमवार को दतिया में कुशवाह, बाल्मीक, मांझी सहित विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजनों और वरिष्ठजनों के साथ बैठक कर संवाद किया तथा जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान भारत सिंह कुशवाह ने भाजपा की नीतियों, संगठन और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने और विकास को प्राथमिकता देने का कार्य कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति, वंशवाद और समाजों के विकास की उपेक्षा करने के आरोप भी लगाए। ये आरोप भारत सिंह कुशवाह द्वारा अपने भाषण के दौरान लगाए गए।

बैठक एवं जनसभा में विभिन्न समाजों के वरिष्ठजन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

मप्र को कर्ज में डूबे रही हैं, मोहन सरकार- घनश्याम सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी

दतिया (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की सरकार प्रदेश को कर्ज में डुबों रही हैं। शासकीय योजनाओं में सिर्फ भ्र्ष्टाचार हो रहा है। पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की

कमलनाथ सरकार ने विधवा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए कर दी थी, भाजपा सरकार ने वह राशि बंद कर दी है। यह बातें दतिया विधानसभा क्षेत्र के लिए चल रहे चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मतदाताओं से जनसंपर्क करते हुए ग्राम डगरई, लरायटा, फुलेरा, चिरुला,गांधारी, लमायचा, चितुवां, बाजनी, चक रामसागर में कही। उन्होंने कहा कि दतिया की जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए जनादेश दिया था। परंतु भाजपा ने षड़यंत्र करके दतिया की जनता पर फिर से चुनाव थोप दिया है। आप सब मिलकर भाजपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाएं।

दामोदर यादव ने गांव चौपाल यात्रा के तहत किया जनसंपर्क

नंदपुर, सैपुरा, रैपुरा और भिटी गांव में ग्रामीणों से संवाद

दतिया (निज संवाददाता)। दतिया विधानसभा उपचुनाव के तहत आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने सोमवार को गांव चौपाल यात्रा के अंतर्गत नंदपुर, सैपुरा, रैपुरा और भिटी गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा अन्य स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान दामोदर यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय, संविधान और सम्मान की राजनीति के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिल रहा है और मतदाताओं से पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। गांव चौपाल यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक भी मौजूद रहे।

आशुतोष तिवारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया जनसंपर्क

बोले– भाजपा का हर वोट दतिया के विकास को देगा नई रफ्तार

दतिया (निज संवाददाता)। दतिया विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने रविवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने ग्राम डगरई, लरायटा, फुलरा-पगरा, करारीखुर्द, चिरूला, चिरूला डेरा, डेरा गंधारी, गंधारी, लमायचा, चितुआ, रावतपुरा सहित कई गांवों और दतिया नगर के वार्ड क्रमांक-11 में घर-घर पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान आशुतोष तिवारी ने कहा कि भाजपा के पक्ष में दिया गया प्रत्येक वोट आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य और दतिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, जिससे विकास की गति लगातार बढ़ रही है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा, 'मैं दतिया का बेटा हूं। जनता की एक आवाज पर उनके घर के दरवाजे तक पहुंचकर सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा।' उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने दतिया में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और जो कार्य अभी शेष हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जाएगा।

जनसंपर्क के दौरान कई स्थानों पर ग्रामीणों ने आशुतोष तिवारी का स्वागत किया। उन्होंने माताओं, बहनों और बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त कर उनके सुख-दुख में हमेशा साथ रहने का भरोसा दिलाया तथा मतदाताओं से भाजपा को विजयी बनाने की अपील की।

बौरेश्वर धाम के विकास की कमान अब युवाओं के हाथ

भिण्ड (निज संवाददाता)। बौरेश्वर विकास समिति के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन विगत दिवस बौरेश्वर धाम परिसर में आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सदस्यों ने त्यागपत्र देकर बौरेश्वर धाम के विकास की कमान अब युवाओं के हाथ सौंप दी है। इस अवसर पर समिति के संयोजक नमोनारायण दीक्षित ने सदस्यों को समिति के प्रयासों से अब तक किए गए कार्यों के बारे में बताया कि तालाब में मौर सिराने के लिए सीढ़ियां, पार्क की व्यवस्था, सत्संग हॉल, धर्मशाला आदि कार्य कराए गए हैं। मन्दिर के जीर्णोद्धार और तालाब के सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। इस कार्य की जिम्मेदारी लेकर अब युवा वर्ग ने संकल्प लिया है। पूर्व समिति के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया है और युवाओं के हाथ में बौरेश्वर धाम के विकास की कमान सौंप दी गई है।

कार्यकारिणी में दिनेश सिंह भदौरिया पूर्व जिला पंचायत सदस्य को अध्यक्ष, अनुराग बौहरे सह अध्यक्ष, सुबोध तिवारी सचिव, अमित भदौरिया एवं सुनील चौधरी उपाध्यक्ष, केतन पुरोहित, मणिकांत शर्मा, दिनेश उपाध्याय, रजत भदौरिया, राजेश दुवे, देवेन्द्र पुरोहित, दीपक कटारे, कृष्ण कुमार पाराशर, इन्द्रप्रकाश पाण्डे आदि शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. इन्द्रप्रकाश त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर किशन बिहारी पांडे, मनहर सिंह भदौरिया आदि उपस्थित रहे।

दतिया उपचुनावः बसई और उनाव क्षेत्र में पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बल का फ्लैग मार्च

ग्रामीणों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील, असामाजिक तत्वों को दी सख्त चेतावनी

दतिया (निज संवाददाता)। आगामी दतिया विधानसभा उपचुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को थाना बसई और थाना उनाव पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक मयूर खण्डेलवाल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चावला के मार्गदर्शन में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने गांवों के प्रमुख

मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों से निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की गई तथा चुनाव के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। पुलिस ने असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने अथवा किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्भय होकर भाग लेने की अपील की है।

सोनम बंगचुग के समर्थन में मौ नगर में युवाओं का प्रदर्शन

- नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

भिड (निज संवाददाता)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सोनम बंगचुग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन भिण्ड जिले के मौ नगर में भी युवाओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज सुबह बारिश में भीगते हुए विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने नगर में रैली निकालकर मौ नगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।

प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने कहा कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दो, भाजपा सरकार जवाब दो' तथा अन्य विरोधी नारे लगाए।

युवाओं का कहना था कि यदि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर और बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ आयोजित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में विक्की जाटव, देवेन्द्र ओझा, प्रदीप कुशवाह, भारत यादव, दलवीर राठौर, नीतेश ओझा, छात्र संगठन और शिक्षक भी शामिल रहे।

सोनम वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने निकाला विरोध मार्च

भिण्ड (निज संवाददाता)। आम आदमी पार्टी जिला भिण्ड द्वारा देश के प्रख्यात वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक के लोकतांत्रिक संघर्ष के समर्थन तथा पेपर लीक प्रकरण में जवाबदेही तय करने एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च शास्त्री चौराहा से चलकर परेड चौराहा और गोल मार्केट तक निकाला गया। मार्च में पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग उठाई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अभिलाख सिंह कुशवाह ने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य बार-बार होने वाले पेपर लीक से बर्बाद हो रहा है। जब एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक युवाओं के हित में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, तब उनकी आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होना आवश्यक है और पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश संगठन मंत्री एवं चंबल संभाग प्रभारी साकेत सक्सेना ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी युवाओं के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनके साथ मजबूती से खड़ी है। यदि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई तो देश का भविष्य प्रभावित होगा। सरकार को राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर छात्रों और युवाओं के हित में तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जिला सचिव शाक्य ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों और ड्रेस के नाम पर कमीशन खोरी चल रही है उसके लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विरोध मार्च के दौरान अशोक जाटव, अंतराम प्रजापति, जयदीप राजावत, एडवोकेट अनिल शर्मा, अनुज पटवा, कमलेश त्रिपाठी, रामकुमार राजपूत, राजेश शाक्य, प्रवेश रावत, अब्दुल मजीद, पवन पुरोहित, पूरन रावत, विनय दुबे, कैलाश भदौरिया, शिवम पंडोरिया, रामपाल कुशवाह, रामबिहारी शाक्य, रामवीर शाक्य, विक्रांत दीक्षित आदि कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नगर पालिका भिण्ड में आधा दर्जन मनोनीत पार्षदों की हुई नियुक्ति

भिण्ड (निज संवाददाता)। मप्र शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भिण्ड जिले के अंतर्गत स्थानीय निकायों में मनोनीत पार्षदों (एल्डरमैन) की नियुक्तियों की घोषणा विभाग के उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला ने कर दी है।

मप्र नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने भिण्ड में गणमान्य नागरिकों को पार्षद के रूप में मनोनीत किया है। जारी आदेश के अनुसार, इन सभी मनोनीत पार्षदों का कार्यकाल वर्तमान परिषद के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

भिण्ड नगर पालिका परिषद के मनोनीत पार्षद

अजीत भदौरिया अहेती पुत्र मोहन सिंह निवासी वार्ड क्र.एक महावीर गंज भिण्ड, मोनू नरवरिया पुत्र शिवनारायण निवासी वार्ड क्र.27 खिड़किया मोहल्ला भिण्ड, आशीष समाधिया पुत्र राजनारायण समाधिया निवासी वार्ड क्र.2 अटेर रोड बड़े हनुमान मन्दिर के पास भिण्ड, नीतेष जैन पत्नी अमित जैन निवासी वार्ड क्र.32 महावीर गंज भिण्ड, सुनील तोमर पुत्र किशन सिंह तोमर निवासी वार्ड क्र.8 शास्त्री नगर गेलेक्सी स्कूल के पास भिण्ड, अनूप पाण्डेय पुत्र रामहरी पाण्डेय निवासी वार्ड क्र.17 गीता भवन चौराहा भिण्ड को मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया है।

विकास को मिलेगी गति

राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों के अनुभवी चेहरों को परिषद में जगह मिलने से नगर के विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को परिषद की बैठकों में मजबूती से उठाने में मदद मिलेगी। नियुक्तियों की खबर मिलते ही समर्थकों में हर्ष की लहर है और नवनियुक्त पार्षदों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है।

गोहद पुलिस ने 3-3 हजार के दो इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार

भिण्ड (निजसंवाददाता)। गोहद थाना पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे तीन-तीन हजार के इनामी दो बदमाशों को बरथरा रोड पर ईंट भट्टे के पास से गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार गत 27 अप्रैल को फरियादी नवल सिंह गुर्जर पुत्र बहादुर सिंह गुर्जर निवासी वार्ड क्र.2 बिहारी नगर गोहद की शिकायत पर 8 नामदर्ज लोगों पर अपराध क्र.88/26 धारा 110, 126(2), 351(3), 3(5) का प्रकरण कायम कर दौराने विवेचना धारा 109, 190, 191 बीएनएस, 25-27 आर्म्स एक्ट की इजाफा की गई। विवेचना के दौरान उक्त आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहे थे जो गिरफ्तारी से बचने के लिए विभिन्न स्थानो पर रह रहे थे।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर तीन-तीन हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था। थाना गोहद पुलिस ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर से फरार दो आरोपियों को बरथरा रोड पर ईंट भट्टे के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें जेआर पर न्यायालय पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी गोहद नरेन्द्र सिंह कुशवाह, उपनिरीक्षक रामनिवास गुर्जर, प्रधान आरक्षक गौरीशंकर, सोनू कुमार, आरक्षक भानु तोमर, भूपेन्द्र जाट, योगेन्द्र तोमर, सागर तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एण्डोरी पुलिस तीन हजार इनामी स्थाई वारंटी किया गिरफ्तार

गोहद (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक भिण्ड सूरज कुमार वर्मा एवं एएसपी प्रदीप पटेल के निर्देशन एवं एसडीओपी गोहद महेन्द्र सिंह गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एण्डोरी विवेक प्रभात के नेतृत्व मे इनामी बदमाश व स्थाई वारंटियों की धरपकड़ हेतु टीम गठित की गई। इसी तारतम्य में सोमवार को न्यायालय गोहद के प्रकरण क्र.100/21 में फरार आरोपी को मुखबिर की सूचना पर ग्राम भूरे का पुरा से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। स्थाई वारंटी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तीन हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी एण्डोरी विवेक प्रभात, सउनि नेतराम सिंह, आरक्षक रजित चौहान, नीरज कुमार, सुनील कुबेर, ज्ञान सिंह की सराहनीय भूमिका रही है।

उत्तर मध्य रेलवे

झॉसी_एम_26_06 | **ई-निविदा सूचना** | दिनांक 17.07.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक / यॉत्रिक, झॉसी, उत्तर मध्य रेल निर्धारित निविदा प्रारूप में निम्नलिखित कार्य हेतु खुली ऑनलाईन निविदायें (ई-टेण्डरिंग) आमंत्रित की जाती हैं।

ई-निविदा सूचना संख्या : झाँसी_एम_26_06

कार्य का उसके स्थान सहित नामः 'झांसी कोचिंग डिपो में प्राथमिक रखरखाव (पी एम), द्वितीयक रखरखाव (एस एम) के दौरान कोचों की मशीनीकृत सफाई, कोचों के लिए टर्न अराउंड अटेंशन (टी आर ए), झांसी कोचिंग डिपो परिसर की 03 वर्ष (1096 दिन) की अवधि के लिए सफाई।'

कार्य की अनुमानित लागत : ₹ 6,62,77,816.71/- | **धरोहर राशिः** ₹ 4,81,400/-

कार्य समापन की अवधिः 03 वर्ष , निविदा बंद करने की तारीख एवं समय : 10.08.2026 बंद होने का समय **15:00 बजें**।, • निविदा दिनांक **10.08.2026** को **15:00** बजे तक ऑनलाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रेल की वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध कराया गया है। **1646/26 (D)**

North central railways | @ CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

परीक्षाओं को पारदर्शी बनाओ धर्मेन्द्र प्रधान स्तीफा दो

- सीटू ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

भिण्ड। संसद जब आवारा हो जाती है तो सड़कों को जन आंदोलन के माध्यम से आवाद होना चाहिए, तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, यह 1975 में राममनोहर लोहिया ने कहा था, ठीक 50 वर्ष वाद 20 जुलाई 2026 को देश के छात्र नौजवानों द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी बनाओ धर्मेन्द्र प्रधान स्तीफा दो का आंदोलन जन आंदोलन बन गया, 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों नौजवानों का संसद मार्च सफल रहा। दूसरी तरफ देश के सभी जिलों में विरोध कार्रवाई कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे गए। भिण्ड में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा व सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू ने उप जिलाधीश राजन नाड़ियां के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया।

संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक वरिष्ठ एडवोकेट देवेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जो वार्ता से डरती है, संसद में विपक्ष के सांसदों के सवालों के जबाब नहीं देते, संसद स्थगित करने का बड़ा रिकार्ड भाजपा मोदी सरकार के नाम है, देश को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो पत्रकार बंधुओं के सवालों के उत्तर नहीं देता और देश का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने मंत्रीमण्डल के सदस्यों के काम की समीक्षा नहीं करता, जो मंत्री द्वारा परीक्षाओं को भी सफलता पूर्वक कराने में अक्षम है वार वार पेपर लीक हो रहे हैं उसे पद से स्वयं त्याग पत्र दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री को त्याग पत्र ले लेना चाहिए था।

सीटू जिला महासचिव अनिल दौनेरिया ने बताया कि लोकतंत्र में वार्ता चर्चा होना जरूरी है, भाजपा मोदी सरकार संवादहीनता को अपनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, दिल्ली में 23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों शिक्षाविद बैज्ञानिक से सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने चर्चा करना उचित नहीं माना, बल्कि संसद मार्च के दौरान भाजपा सरकार की पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज में सैकड़ों छात्रों को चोटे आई है। ज्ञापन के दौरान एडवोकेट देवेन्द्र सिंह चौहान, अनिल दौनेरिया, एडवोकेट सूरज रेखा त्रिपाठी, नदीम खान, एडवोकेट गजेन्द्र सिंह, एडवोकेट रवी बघेल, नरेश भटनागर, रुबी खान, एडवोकेट मजहर नारायण, एडवोकेट अजीत कुमार, एडवोकेट आदित्य, एडवोकेट राजप्रताप आदि उपस्थित रहे।

उत्तर मध्य रेलवे

पत्रांकः- Dy. CE-JHSW-99 | दिनांकः 18.07.2026

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये उप मुख्य इंजीनियर/कारखाना/झाँसी हेतु आनलाईन ई-टेन्डरिंग के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई-निविदा सूचना संख्याः डिप्टी सी.ई.-झांसी डब्ल्यू-99, **कार्य का नामः** झाँसी में वैगन मरम्मत कारखाना में डीलक्स शौचालय सहित नए टैंक वैगन कार्यालय का निर्माण।

अनुमानित लागत (₹ में): ₹ 54,28,541.60 (चौवन लाख अठ्ठाईस हजार पांच सौ इकतालीस रूपये और साठ पैसे मात्र।)

अमानत राशि (₹ में): ₹ 1,08,600/- | **निविदा प्रपत्र कर मूल्य रूपयेः** कुछ नहीं।

निविदा बन्द होने की तिथि एवं समयः 11.08.2026, 15:30 बजे।

स्वीकृत पत्र जारी समय होने से कार्य समापन/अवधि की तिथिः 12 माह।

नोटः पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के साईट www.ireps.gov.in पर देखें। **1658/26 (MG)**

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

एमजेएस कॉलेज में युवा संगम रोजगार मेला कल

-13 कंपनियों द्वारा की जाएगी नि:शुल्क भर्ती

भिण्ड (निज संवाददाता)। जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय भिण्ड, आईटीआई तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड द्वारा युवा संगम रोजगार, अप्रेंटिस तथा स्वरोजगार मेला का आयोजन 22 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शा. एमजेएस महाविद्यालय भिण्ड में किया जाएगा।

मेले में क्विक आईटी सालूशन एण्ड कंटलजेंसी ग्वालियर द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवाओं के लिए असिस्टेंट मैनेजर तथा रिलेशनशिप मैनेजर, आमधनी प्रालि गुजरात द्वारा 18 से 25 आयु वर्ग के 10/ 12वीं पास युवाओं के लिए अप्रेंटिश एवं ऑपरेटर, डिफरेंस मेनेजमेंट डेवलमेंट इंडिया प्रालि लखनऊ द्वारा 18 से 35 आयु वर्ग के न्यूनतम 10वीं पास एवं 12वीं पास युवाओं के लिए अप्रेंटिश एवं ऑपरेटर, एक्सिक बैंक गुडगांव द्वारा 18 से 23 आयु वर्ग के स्नातक युवाओं के लिए असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क की भर्ती की जाएगी।

इसी प्रकार एलआईसी भिण्ड द्वारा 18 से 35 आयु वर्ग के 12वीं पास युवाओं के लिए फील्ड ऑफिसर, एमपीएमके वीवीसीएल भिण्ड द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं कंप्यूटर, बीई, आईटीआई युवाओं के लिए स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन, जमुना ऑटो पार्ट्स मालनपुर द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं एवं आईटीआई पास युवाओं के लिए ऑपरेटर, ट्रेनीज, कौशल विकास केन्द्र ग्वालियर द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं के लिए ट्रेनीज, विराट बायोटेक प्रालि गुजरात द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं के लिए सेल्समैन, ग्रेट आर्गेनिक डायमंड प्रालि सागर द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं के लिए एडवाइजर के पदों पर भर्ती होगी।

कोसमोस प्रालि ओरंगाबाद द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के स्नातक युवाओं के लिए ऑपरेटर, नोकरी फाई डाट काम भिण्ड द्वारा 18 से 26 आयु वर्ग के स्नातक युवाओं के लिए ब्रांच मैनेजर, गौतम सोलर प्रालि भिमानी द्वारा 18 से 26 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं के लिए असिस्टेंट ऑफिसर पद पर भर्ती की जावेगी साथ ही कंपनियों द्वारा 14 हजार से 40 हजार तक वेतन, स्टाई फण्ड दिया जाएगा। आवेदक साक्षात्कार के समय 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की मूल अंकसूची एवं अपने समस्त मूल-प्रमाण पत्र सहित एवं पासपोर्ट साइज के तीन फोटोग्राफ लेकर आवें। प्लेसमेंट ड्राईव में उपस्थित होने वाले युवकों को कार्यालय द्वारा कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

कल्लू मुदगल और संदीप बने कांग्रेस के दतिया उपचुनाव में प्रभारी

भिण्ड (निज संवाददाता)। दतिया उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवादल की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजकिशोर शर्मा कल्लू मुदगल और भिण्ड सेवादल जिलाध्यक्ष संदीप मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर सेवादल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने दोनों नेताओं को अपनी कोर कमेटी का सदस्य मनोनीत किया है। दोनों नवनियुक्त प्रभारी दतिया में लगातार रहकर बूथ मैनेजमेंट, प्रचार-प्रसार, साथ ही सेवादल की प्रतिदिन निकलने वाली प्रभात फेरी के संचालन को संपादित करेंगे। सेवादल की तरफ से इस नियुक्ति से दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जमीनी मजबूती और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होने की उम्मीद है।

आम सूचना

सभी जन आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री सुरेखा जाटव पुत्री श्री मुरारीलाल जाटव (नया नाम) के लिये यह घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री का पुराना नाम सुलेखा पुत्री मुरारी था अब में अपनी पुत्री का पूर्व कुलनाम सुलेखा को छोडकर नया कुल नाम सुरेखा जाटव रख रहा हूँ अब मेरी पुत्री को सभी लोग सुरेखा जाटव पुत्री मुरारीलाल जाटव के नाम से पुकारा जावे। अम व खासजन को सूचित हो। यह आम सूचना मेरी पुत्री के सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यों में काम आवे। यही नाम लिखा व पढ़ा जावे। मेरी पुत्री का आधारकार्ड नं. 8728 1256 6848 है।

सूचनाकर्ता
मुरारीलाल जाटव पुत्र श्री पहलवान
निवासी चंबल कॉलोनी मुरैना
जिला मुरैना (म.प्र.) 476001

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं.: JHS/Commercial/E-Auction/2026/177 | दिनांकः 16.07.2026

ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), उत्तर मध्य रेलवे, झांसी द्वारा निम्न दी गयी श्रेणियों के अनुसार ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है :-

श्रेणीः पार्किंग | **केटलोग संख्याः** झाँसी-पार्किंग-63

एसेट्स डिटेल्सः झाँसी मंडल के अलग-अलग श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के पार्किंग ठेके हेतुः-			**ई-नीलामी प्रारम्भ की तिथि व समय**	**ई-नीलामी समाप्त की तिथि व समय**
क्र.सं.	**स्टेशन/केटेगरी**	**स्टेशन/स्थान**	दिनांक 03.08.2026 को समय- 12:00 से	दिनांक 03.08.2026 को समय- 12:30 तक
1	एनएसजी-2	ग्वालियर पश्चिम		

नोट- उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाइन वेवसाइट- **www.ireps.gov.in** के **e-auction module** के माध्यम से की जाएगी। लॉट अनुसार विवरण उपर्युक्त केटलॉग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध है। **1641/26 (A)**

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

देश में सर्वश्रेष्ठ बने मध्यप्रदेश पुलिस : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस में 25 हजार पदोन्नतियों के लिए दी बधाई

नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य हो

नशामुक्ति अभियान के लिए निरंतर कार्य हो

अन्य प्रांतों की सीमाओं के निकट नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन को रोकने के निर्देश

आगामी त्योहारों पर बनी रहे बेहतर कानून व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस मुख्यालय में की वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हाल ही में राज्य सरकार के पदोन्नति अभियान में पुलिस में सर्वाधिक पदोन्नतियां हुई हैं। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखने, अपराधों पर सख्त नियंत्रण और अधिक परिणाम लाने का कार्य किया जाए। मध्यप्रदेश पुलिस देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाए, इसके लिए प्रयासों में कमी नहीं रखना है। नागरिकों में पुलिस के प्रति भरोसा है, इसे कायम रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस में विभिन्न स्तरों के लगभग 25 हजार पदों पर की गई पदोन्नति की कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी करें। नागरिकों को बेहतर कानून व्यवस्था का लाभ मिले। पुलिस अमला त्योहारों के अवसर पर मुस्तैद रहे।

नक्सलमुक्त क्षेत्रों में विकास में सहभागी बने पुलिस

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद के खात्मे के लिए जिस दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए उपलब्धि प्राप्त की गई, उसमें मध्यप्रदेश के नक्सल क्षेत्र को भी सामान्य बनाने में सफलता मिली है। नक्सलवाद के खत्म होने के पश्चात विकास कार्यों की गति बढ़ानी है और ऐसे इलाकों में पुलिस अमला भी सकारात्मक कार्यों से जुड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है।

नशा मुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन करे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में नशामुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन होता रहे। हाल ही में अभियान के अंतर्गत 'नशे से दूरी है जरूरी' स्लोगन को लोकप्रियता मिली है और नागरिकों ने नशामुक्ति की शपथ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित नशामुक्ति अभियान के लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए। नक्सलवाद से मुक्ति की तरह नशा मुक्ति के लिए तय समय-सीमा के पहले ही मध्यप्रदेश अच्छा कार्य करके दिखाए। इस क्रम में पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय कर शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाने में सहयोगी बनें। श्रेष्ठ कार्य के लिए नशामुक्ति अभियान में योगदान देने वालों को पुरस्कृत भी करें। अन्य राज्यों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण किया जाए।

उद्योग क्षेत्र और अन्य संस्थानों को उपलब्ध करवाएं सुरक्षा स्टाफ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हो रहा है, इस नाते आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी हो गई है। विभिन्न संस्थानों और उद्योग क्षेत्र के लिए एसआईएसएफ से लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ प्रदान करवाने का कार्य हो। भविष्य की दृष्टि से विकास के क्षेत्रों और सामाजिक स्तर पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की भी तैयारी रखें। वरिष्ठ अधिकारी हर समस्या के समाधान के प्रयास करें।

प्रमोशन और नियुक्ति का अभियान जारी रहे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य शासन प्रदेश में नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था और सदभाव के वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रहा है। इस सिलसिले में लगभग 25 हजार पदोन्नतियां हाल ही में विशेष अभियान के अंतर्गत विभिन्न पदों पर की गई हैं। आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक और निरीक्षक के पदों पर बरसों से पदोन्नतियां नहीं हुई थीं। अन्य विभागों के साथ पुलिस विभाग में पदोन्नतियों का लाभ आमजन को बेहतर सेवाओं के रूप में मिलेगा। आगे भी पद रिक्त होने की स्थिति में डीपीसी कर प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसके लिए कैलेंडर तैयार किया जाए। पद पूर्ति के लिए बैकलॉग समाप्त किया जाए। स्वीकृत पद भरने में विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी तरह पुलिस में प्रत्येक स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य बिना विलंब किया जाए। प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया, भारिया की नियुक्तियों पर ध्यान दें। इन जनजातियों के रहवास के छह जिलों में योग्य युवाओं को पुलिस सहित विभिन्न सेवाओं में रुचि के अनुरूप भर्ती पर भी विचार किया जाए।

अब हर जिले में पुलिस बैंड में पर्याप्त पद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक जिले का अपना बैंड ग्रुप तैयार हो जाए, यह सुनिश्चित करें। अधिकांश जिलों में पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेष?जिलों में यह कार्य पूर्ण किया जाए। बैठक में पुलिस हाऊसिंग बोर्ड के कार्यों, वाहनों की आवश्यकता, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीन ऑफ क्राइम पर जाने के लिए एफएसएल की तरह व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश में मनाया जाएगा महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

गुरु पूर्णिमा से पहले ही कराए सभी सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण

महर्षि सांदीपनि के जीवन चरित्र एवं योगदान पर लघु पुस्तिका प्रकाशित करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने की गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजन की तैयारियों की समीक्षा

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय है, वंदनीय हैं। गुरु ही हमें 'गु' (अज्ञान के अंधकार) से 'रु' (ज्ञान-विज्ञान की रश्मि/प्रकाश) की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा अपने गुरुजनों की सेवा, वंदना और उनका आशीर्वाद पाने का प्रमुख उत्सव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परम्परा तथा भारतीय गुरु-शिष्य परम्परा के आदर्शों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशव्यापी 'महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व' का आयोजन किया जाये। इसमें स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थानों तथा खेल, नाटक, चित्रकला, संगीत एवं अन्य कला संस्थानों की भी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवारको मध्यप्रदेश विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक-1 में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभी प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा चल रहा है। प्रदेश में जितने भी सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण होना शेष है, उनका लोकार्पण गुरु पूर्णिमा से पहले करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि सांदीपनि योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के गुरु थे। उन्होंने तत्समय अमीर और गरीब सभी छात्रों को विद्या दान देकर राष्ट्र भक्ति का परिचय दिया। वहीं देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को व्यवस्थित करने में प्रभावी योगदान दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महर्षि सांदीपनि के जीवन चरित्र एवं गुरुकुल शिक्षा पद्धति के प्रसार में उनके वैशिष्ट्य और योगदान पर केंद्रित एक लघु पुस्तिका का प्रकाशन करायें और सभी विद्यालयों में वितरित करायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्?थाओं में गुरू-पूजन आयोजन किया जाये। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष विद्यालयों में मनाये जाने वाले मित्रता दिवस पर श्रीकृष्ण-सुदामा के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाये।

गुरू पूर्णिमा को जनभागीदारी का उत्सव बनाये

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा 'महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व' को जनभागीदारी का उत्सव बनाया जाए, जिससे विद्यार्थियों और युवाओं में अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था सुदृढ़ हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ-साथ निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी इस आयोजन से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जाए, ताकि गुरु-शिष्य परम्परा का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और इसे नई पीढ़ी तक सशक्त रूप से पहुंचाया जा सके। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, कार्यक्रमों के स्वरूप तथा विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई) के दिन शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाले कार्यक्रमों में सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा/चित्र पर माल्यार्पण, सरस्वती वंदना, गुरुजनों का स्वागत-सत्कार-सम्मान, व्याख्यान/उद्बोधन, छात्र-शिक्षक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्?थान विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्?वविद्यालयों में साहित्?यिक एवं सांस्?कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा ही किए जायें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा और महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के आयोजन से समाज की भी सक्रिय सहभागिता के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, उच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री श्रीराम तिवारी, संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले सीजी पॉवर के एमडी श्री कौल

सीहोर की निर्माण इकाई के 3 सितंबर को होने वाले लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित कक्ष में सी.जी. पॉवर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमर कौल ने सौजन्य भेंट की। सी.जी. पॉवर कंपनी, ट्रांसफॉर्मर्स और उसके कम्पोनेंट्स का उत्पादन करती है। कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश के ग्वालियर में अपनी औद्योगिक इकाई की स्थापना की जा चुकी हैं। कंपनी की ऐसी ही एक उत्पादन इकाई सीहोर में स्थापित हो रही है। सी.जी. पॉवर के एमडी श्री कौल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपनी सीहोर स्थित निर्माण इकाई के 3 सितंबर 2026 को होने वाले लोकार्पण समारोह का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध किया।

आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान

बायोमेट्रिक आधारित प्री-ऑथराइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

भोपाल (निज संवाददाता)। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को 'बेस्ट परफार्मिंग लार्ज स्टेट- हाइयेस्ट प्री-ऑथोराइजेशंस विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन' श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधारित प्री-ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी, पारदर्शी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिये आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश की टीम को बधाई दी है।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीक आधारित सुशासन और जनहितकारी कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश की टीम, जिला अधिकारियों, चिकित्सालयों और योजना से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक (चिंतन शिविर) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव द्वारा आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविंद शाह को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल, संयुक्त सचिव श्री किरण गोपाल वास्का सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं यूआईडीएआई (आधार) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समरदोंग सुरंग में 27 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

गंगटोक, 20 जुलाई (हि.स.)। दक्षिण सिक्किम के समरदोंग में एनएचपीसी की एक सुरंग में हुए हादसे में राहत और बचाव का काम जारी है। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर करीब 27 लोग फंसे हो सकते हैं। नामची जिले की जिलापाल अनूपा तामलिंग ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सुरंग के अंदर करीब 27 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि, अभी असली संख्या की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सुरंग के अंदर की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की एक टीम सुरंग में गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरए की टीम के बाहर लौटने के बाद ही टनल के अंदर मजदूरों की संख्या और उनकी हालत के बारे में साफ जानकारी मिल पाएगी।

जिलापाल ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों के मुताबिक, सुरंग के अंदर काम कर रहे मजदूरों ने धमाके जैसी आवाज सुनी। इसके बाद कुछ मजदूर सुरंग से बाहर भागने में कामयाब रहे, जबकि कुछ अंदर फंसे हुए हैं। अभी बचाव और राहत का काम चल रहा है और अभी तक टनल से किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस और इमरजेंसी सर्विस सुरंग स्थल पर मौजूद हैं और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार दोपहर को समरदोंग में एनएचपीसी की एक सुरंग में अचानक कथित गैस लीक का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद सुरंग के अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि सुरंग के अंदर क्या हुआ और अभी वहां कितने लोग फंसे हुए हैं।

मप्र के भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 पर 21-22 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यशाला

- प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर होगा मंथन, खाद्य मंत्री राजपूत करेंगे शुभारंभ

भोपाल, 20 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 : प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 21 एवं 22 जुलाई 2026 को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा।

जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला में नीति आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य प्रो. राजेश चंद्र, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेन्द्र कुमार मल्होत्रा, खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी तथा मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव श्रीमन शुक्ला भी विचार व्यक्त करेंगें।

उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भविष्य की रणनीति पर व्यापक विचार-विमर्श करना है। विभिन्न तकनीकी सत्रों में खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण सुरक्षा, हितग्राहियों तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच तथा अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यशाला में नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नवाचारों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों तथा भविष्य की कार्ययोजना पर भी मंथन किया जायेगा।

मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की प्रशासकीय अधिकारी पूर्णिमा शर्मा ने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव एवं अनुशंसाएं प्राप्त होंगी, जो भविष्य की नीतियों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होंगी।

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में समृद्धि हाइवे पर हादसे में छह लोगों की मौत

मुंबई, 20 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सालोद में समृद्धि हाइवे पर सोमवार तडक़े हुए विचित्र सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के चार लोग और दूसरे वाहन के ड्राइवर और क्लीनर शामिल हैं। सूचना पाकर पुलगांव पुलिस और हाइवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंचीं। वर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि समृद्धि हाइवे पर नागपुर जाने वाले रास्ते पर एक इथेनॉल ट्रक पलटने से ट्रैफिक जाम हो गया था। इसलिए, गाडियों को धीरे-धीरे दूसरी लेन में निकाला जा रहा था। इसी बीच, पीछे से आ रहे मिर्च से भरे एक आयशर ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रक के नीचे दब गई। इसी दौरान ट्रक में आग लग गई। इस आग की लपटों में झुलसकर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। ट्रक के नीचे दबी कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कार सवार अंकुश राउत, राजेश टिपले, जान्हवी टिपले और सुषमा टिपले, आयशर ट्रक ड्राइवर संजय कुमार और क्लीनर समरजीत पाल के रूप में हुई है। संजय धनजीपुर, उत्तर प्रदेश और समरजीत पाल गधरियनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्धा के रहने वाले राजेश टिपले की दो बेटियों में से एक का एडमिशन एमबीए में हुआ था। रविवार को वे अपनी बेटी को पुणे छोड़ने गए थे। रविवार को देर रात वे वर्धा के लिए निकले थे, लेकिन वर्धा में समृद्धि हाइवे पर हुए हादसे में उनके साथ परिवार के चार लोगों की मौत हो गई।